घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 193- शुक्रवार 15 - मई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

चुनाव आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा की

नई दिल्ली,14 मई 2026। चुनाव आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची अपडेट करने से जुड़ी प्रक्रिया विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) करने का निर्देश जारी कर दिया है। पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान 36.73 करोड़ वोटरों का वेरिफिकेशन होगा। एसआईआर के पहले दो चरणों में 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 59 करोड़ मतदाता शामिल थे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरा देश कवर होगा। आंध्र प्रदेश 4,16,16,061,अरुणाचल प्रदेश 8,87,607,चंडीगढ़ 5,18,663, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव 4,27,849,हरियाणा 2,06,63,155, झारखंड 2,64,89,777 मतदाता, कर्नाटक 5,55,74,064, महाराष्ट्र 9,86,64,413, मणिपुर 20,91,999, मेघालय 23,43,252, मिजोरम 8,75,004, नागालैंड 13,56,858, दिल्ली 1,48,23,234, ओडिशा 3,34,33,659,पंजाब 2,14,56,297, सिक्किम 4,71,094, त्रिपुरा 28,97,674, तेलंगाना 3,39,20,705

और उत्तराखंड 79,76,466 शामिल हैं। मतदाता सूची अपडेट करने के दौरान 3.94 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर 36.73 करोड़ मतदाताओं से मिलेंगे। इसमें उनकी सहायता 3.42 लाख बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) करेंगे। बीएलए राजनीतिक दलों की ओर से गणना चरण के दौरान नियुक्त किये जाते हैं। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध किया है कि वे प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए बीएलए नियुक्त करें। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एक संदेश में कहा,'मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तीसरे चरण में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और अपने गणना फॉर्म भरें। आयोजन का उद्देश्य मतदाता सूची में केवल पात्र मतदाताओं को ही शामिल करना और अपात्र व्यक्ति का हटाना है। 'आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार ओडिशा,मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर के लिए ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली (ड्राफ्ट रोल) 5 जुलाई को प्रकाशित होगी,जबकि अंतिम निर्वाचक नामावली 6 सितंबर को जारी की जाएगी। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के लिए ड्राफ्ट रोल 10 जुलाई और अंतिम रोल 11 सितंबर को प्रकाशित होगा। उत्तराखंड के लिए ड्राफ्ट रोल 14 जुलाई और अंतिम रोल 15 सितंबर को जारी होगा। आंध्र प्रदेश,अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित होगी,जबकि अंतिम नामावली 22 सितंबर को जारी की जाएगी। तेलंगाना और पंजाब के लिए ड्राफ्ट रोल 31 जुलाई और अंतिम रोल 01 अक्टूबर को प्रकाशित होगा। कर्नाटक,मेघालय, महाराष्ट्र,झारखंड और दिल्ली के लिए ड्राफ्ट रोल 5 अगस्त को और अंतिम रोल 7 अक्टूबर को जारी होगा। नागालैंड के लिए प्रारूप निर्वाचक नामावली 20 सितंबर और अंतिम नामावली 22 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।

केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे वीडी सतीशन,हाईकमान ने लगाई मुहर

नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम,14 मई 2026। आखिरकार लंबे समय तक ऊहापोह के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने केरल के मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने इस पद के लिए वीडी सतीशन का नाम फाइनल किया है। वो प्रदेश के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी में लोग इसे नई पीढ़ी के औपचारिक आगमन के रूप में देख रहे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने यह ऐलान दिल्ली में किया, जिसमें प्रमुख रूप से दीपा दासमुंशी, मुकुल वासनिक और अजय माकन शामिल रहें। यह फैसला, जिसे काफी समय तक टाला गया था, कांग्रेस ने अपने खास नाटकीय अंदाज में घोषित किया। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल अंतिम दौर की चर्चाओं के दौरान दिल्ली में मौजूद थे। नेतृत्व का फैसला बताने से पहले उन्हें राहुल गांधी के साथ बैठक के लिए बुलाया गया। इस बीच, वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला को राहुल गांधी का निजी फोन आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि अब फैसला हो चुका है और सतीशन को मंजूरी मिल गई है। सतीशन के लिए यह पद उनकी राजनीतिक यात्रा की बड़ी उपलब्धि है। यह फैसला केरल में लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी और चुनावी हार के बाद कांग्रेस के खुद को नए तरीके से तैयार करने की कोशिश को भी दिखाता है। कोच्चि जिले में जन्मे सतीशन इस महीने के आखिर में 62 साल के हो जाएंगे। उन्होंने अपनी पहचान गुटबाजी की राजनीति से नहीं बल्कि विधानसभा में अच्छे प्रदर्शन और संगठन में लगातार काम करके बनाई है। पेशे से वकील सतीशन ने 2001 में परावुर से विधानसभा

चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के तेज और प्रभावशाली वक्ताओं में अपनी पहचान बनाई। आंकड़ों, तीखे व्यंग्य और दमदार बोलने के अंदाज के कारण सतीशन वामपंथी दलों के लिए बड़ी चुनौती बन गए। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें सबसे बड़ी सफलता ऐसे समय में मिली जब कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में यूडीएफ की बड़ी हार के बाद सतीशन को अचानक विपक्ष का नेता चुना गया। शुरुआत में कई लोगों ने उन्हें अंदरूनी खींचतान के बीच एक समझौता उम्मीदवार माना था। सतीशन ने इस जिम्मेदारी को अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करने का बड़ा मौका बना लिया।

सोने की तस्करी का मामला हो, एआई कैमरे से जुड़े आरोप हों या कानून-व्यवस्था को लेकर विजयन सरकार पर लगातार हमले सतीशन ने खुद को केरल में वामपंथी सरकार के खिलाफ सबसे प्रमुख और आक्रामक नेता के रूप में स्थापित किया।

असम में 21 करोड़ की हेरोइन व अफीम के साथ पांच तस्कर गिरफ्तार

गुवाहाटी,14 मई 2026। असम में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कामरूप पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अमीनगांव में एक बस से करीब 21 करोड़ 36 लाख मूल्य की हेरोइन और अफीम बरामद की है। इस मामले में पांच कथित तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। असम पुलिस के सीपीआरओ ने गुरवार को बताया कि, गुप्त सूचना मिली थी कि मणिपुर के क्वाक्टा से पड़ोसी राज्य की ओर जा रही बस संख्या एएस 06 एसी 7555 के जरिए भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है। सूचना में यह भी बताया गया था कि बस में कोई सामान्य यात्री नहीं है और उसमें केवल तस्कर सवार हैं। सूचना के आधार पर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने अमीनगांव में बस को रोककर तलाशी अभियान चलाया। जांच के दौरान बस में बने गुप्त खाने से 197 साबुन के डिब्बों में छिपाकर रखी गई 2.561 किलो हेरोइन और 8 किलो अफीम बरामद की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में अब्दुल लतीफ (33), मोहम्मद ताहेर अली (38), मोहम्मद इस्लामुद्दीन (38), मोहम्मद लतीप (30) और मोहम्मद अजमेर (37) को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मणिपुर के विभिन्न क्षेत्रों के निवासी बताए गए हैं।

शुवेंदु अधिकारी सरकार का बड़ा फैसला

पश्चिम बंगाल के स्कूलों में अब राष्ट्रगान के साथ गूंजेगा वंदे मातरम्

नई दिल्ली,14 मई 2026। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली के दौरान वंदे मातरम् गाना अनिवार्य कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा

गया है कि हर छात्र को स्कूल शुरू होने से पहले सुबह की प्रार्थना सभा में वंदे मातरम् गाने में भाग लेना होगा। स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों को आदेश दिया गया है कि इस फैसले का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अगले सोमवार से राज्य के सभी स्कूलों में वंदे मातरम् को प्रार्थना गीत के रूप में शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से 13 मई को जारी पत्र में कहा गया कि मॉर्निंग असेंबली में क्लास शुरू होने से पहले वंदे मातरम् का गायन अनिवार्य किया जाए ताकि राज्य के सभी स्कूलों में सभी छात्र इसे गाएं। सरकार की ओर से स्कूलों को यह भी कहा गया है कि इस प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखा जाए और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाए, ताकि आदेश के पालन का प्रमाण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में पोस्ट किया। अब तक राज्य के स्कूलों में मुख्य रूप से राष्ट्रगान 'जन गण मन' गाया जाता था। पिछले कुछ वर्षों में तत्कालीन टीएमसी सरकार ने 'बांग्लार माटी बांग्लार जल' को भी राज्य गीत के रूप में शामिल किया था।

CGPSC 2021 भर्ती विवाद : हाईकोर्ट के आदेश के बाद 11 चयनित डिप्टी कलेक्टरों को मिली पोस्टिंग

रायपुर,14 मई 2026। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग2021 भर्ती विवाद मामले में चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से जांच और कानूनी विवाद के चलते इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी हुई थी। बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने 11 चयनित डिप्टी कलेक्टरों को पोस्टिंग और जॉइनिंग आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल सीजीपीएससी 2021 परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी समेत कुल 44 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इनमें से चार अभ्यर्थियों के खिलाफ सीबीआई विशेष अदालत में चार्जशीट पेश कर चुकी है। ये चारों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। बाकी 40 चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नियुक्ति देने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि उनके खिलाफ अब तक न तो आरोप तय हुए हैं और न ही किसी प्रकार के ठोस साक्ष्य मिले हैं।

वैश्विक अनिश्चितता के बीच ब्रिक्स से रचनात्मक और स्थिर करने वाली भूमिका की बढ़ रही उम्मीदें : जयशंकर

नई दिल्ली,14 मई 2026। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने गुरुवार को ब्रिक्स 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच यह उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स वैश्विक अनिश्चितता, संघर्षों और आर्थिक चुनौतियों के बीच एक 'रचनात्मक और स्थिर करने वाली भूमिका निभाएगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत मंडपम में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में ओपनिंग स्पीच देते हुए कहा, 'भारत की अध्यक्षता आपके सपोर्ट की तारीफ करती है, जिसने हमारे काम की लगातार तरक्की में मदद की है।' बता दें, 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। मौजूदा ग्लोबल हालात पर जोर देते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा

कि यह मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बड़े बदलाव और अस्थिरता है। उन्होंने कहा, 'हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब अंतरराष्ट्रीय संबंधों में काफी उतार-चढ़ाव हैं, चल रहे झगड़े, आर्थिक अनिश्चितताएं और व्यापार, तकनीक और जलवायु को लेकर चुनौतियां वैश्विक माहौल को बना रही हैं। ' ब्रिक्स समूह के महत्व पर जोर देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, 'खासकर उभरते बाजारों और विकासशील देशों से यह उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स एक संरचनात्मक और स्थिर करने वाली भूमिका निभाएगा। ' चल रही बातचीत के महत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चर्चाओं ने बड़े वैश्विक और क्षेत्रीय विकास पर सोचने और सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के प्रैक्टिकल तरीकों को खोजने का मौका दिया। जलवायु से जुड़ी चिंताओं को लेकर भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि क्लाइमेट चेंज एक जरूरी ग्लोबल मुद्दा बना हुआ है जिस पर मिलकर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'क्लाइमेट चेंज एक बड़ी चिंता बनी हुई है। हमारी बातचीत में बराबरी और आम लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए सतत विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। ' उन्होंने ग्लोबल ऑर्डर पर तकनीक में तरक्की के बढ़ते असर पर भी जोर दिया और कहा कि इन विकास का इस्तेमाल अच्छे शासन और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए।

चुनाव बाद हिंसा मामले की सुनवाई में कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी,वकील के रूप में हुईं पेश

कोलकाता,14 मई 2026। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को चुनाव बाद हिंसा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचीं। वह अधिवक्ताओं की पोशाक में अदालत परिसर में नजर आईं। सुबह करीब 11 बजे ममता बनर्जी अचानक हाई कोर्ट परिसर पहुंचीं। काला गाउन पहनकर अदालत पहुंचीं ममता को देखकर परिसर में मौजूद लोगों और वकीलों के बीच हलचल मच गई। जानकारी के अनुसार वह चुनाव बाद हिंसा से संबंधित एक जनहित याचिका में पक्ष रखने के लिए अदालत पहुंची। यह मामला मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन की खंडपीठ में सुनवाई के लिए

सूचीबद्ध है। बताया जा रहा है कि इसी मामले में दलील पेश करने के उद्देश्य से ममता अदालत पहुंचीं। राज्य में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विभिन्न इलाकों में हिंसा और तनाव की घटनाओं के आरोप सामने आए हैं। इन्हीं घटनाओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी के पुत्र और अधिवक्ता शीर्षान्य बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

मप्र के देवास में पटाखा फैक्टरी में विस्फोट...तीन की मौत,12 मजदूर घायल

देवास,14 मई 2026। मध्य प्रदेश के देवास जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम टोंककला के समीप स्थित एक पटाखा फैक्टरी में गुरुवार को जोरदार विस्फोट होने बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में तीन श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 12 घायल हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया और घटना की जांच के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ग्राम टोंककला स्थित पटाखा फैक्टरी में सुबह करीब 10.30 बजे जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद फैक्टरी में भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैलने लगी, जिससे अंदर मौजूद मजदूरों को

बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे में तीन श्रमिकों की मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका प्रकट की जा रही है। पटाखा फैक्टरी के चारों ओर धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई है। यहां काम कर रहे श्रमिक बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी और बचाव दल कर्मी मौके पहुंचे।

बंगाल में गौ हत्या पर सख्ती, सार्वजनिक स्थानों पर वध पर सरकार ने लगाई रोक

कोलकाता,14 मई 2026। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार ने राज्य में गौ हत्या और सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। प्रदेश सरकार ने पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम,1950 को सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर पशु वध पर रोक लगा दी है।

राज्य में नई सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यकों के त्यौहार कुर्बानी से पहले ये फैसला सुर्खियों में है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि गाय,बैल,सांड, बछड़ा,भैंस और अन्य मवेशियों का वध बिना वैध प्रमाण-पत्र के नहीं किया जा सकेगा।

सत्ता संभालते ही विजय ने 16 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स को दिया तोहफा,दो फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता...

चेन्नई,14 मई 2026। सीएम विजय ने तमिलनाडु के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी का एलान किया। इस बढ़ोतरी के बाद डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। सरकार ने इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना है। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि इस फैसले से करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किए जाने के

बाद तमिलनाडु सरकार ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को समान लाभ देने का निर्णय लिया है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली सरकार कर्मचारियों और शिक्षकों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है, जो राज्य में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार के अनुसार, डीए बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर सालाना करीब 1,230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके बावजूद कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राशि आवंटित करने का फैसला लिया गया है।

महिला योजना पर सियासत : वहीं तमिलनाडु में 'कलाइग्नार मगलीर उरिमाई थोगई' की मई महीने की किस्त में देरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि हर महीने 15 तारीख तक दी जाने वाली 1,000 की सहायता राशि अब तक क्यों जारी नहीं की गई।

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक

खाद्य सचिव की लोगों से अपील-भीड़ लगाकर खरीदी न करें...

रायपुर,14 मई 2026। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल एवं डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आम नागरिकों को किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले द्वारा स्पष्ट किया गया है कि प्रदेश के ऑयल डिपो को नियमित रूप से आवश्यकतानुसार पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति हो रही है तथा वितरण व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। खाद्य सचिव ने जानकारी दी कि प्रदेश में वर्तमान में कुल 2516 पेट्रोल/डीजल पंप संचालित हैं। राज्य में पेट्रोल का 45,474 किलोलीटर तथा डीजल का 84,654 किलोलीटर स्टॉक उपलब्ध है। वहीं पेट्रोल की दैनिक

आवश्यकता 3,635 किलोलीटर तथा डीजल की दैनिक आवश्यकता 5,873 किलोलीटर है। आज प्रदेश के विभिन्न ऑयल डिपो में 6,551 किलोलीटर पेट्रोल तथा 4,760 किलोलीटर डीजल प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि रायपुर शहर में कुल 326 पेट्रोल/डीजल पंप हैं, जिनमें से 35 पंप अस्थायी रूप से ड्राई आउट हैं। इसी प्रकार बिलासपुर शहर में कुल 156 पेट्रोल/डीजल पंप हैं, जिनमें से 13 पंप ड्राई आउट हैं। इन सभी ड्राई आउट पंपों को यथाशीघ्र स्टॉक उपलब्ध कराने के लिए ऑयल कंपनियों के डिपो से लगातार आपूर्ति की जा रही है। विगत दो दिनों में कुछ पेट्रोल/डीजल पंपों के ड्राई आउट होने के कारण अफवाह एवं घबराहट की स्थिति बनी, जिससे आम लोगों द्वारा पेट्रोल एवं डीजल की खपत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई। मांग में अचानक हुई इस वृद्धि के कारण कुछ स्थानों पर कृत्रिम अभाव की स्थिति निर्मित हुई। खाद्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में पेट्रोल एवं डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। उन्होंने आम उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि वे किसी भी भ्रम अथवा अफवाह से प्रभावित होकर पैनिक खरीदी अथवा ईंधन का अनावश्यक संग्रहण न करें।

छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड के रिजल्ट जारी

12वीं में 71% और 10वीं में 58.39% स्टूडेंट्स पास,दोनों कक्षाओं में लड़कियां आगे रहीं

रायपुर,14 मई 2026। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बुधवार को छत्तीसगढ़ स्टेट ओपन स्कूल की ओर से आयोजित हाई स्कूल (10वीं) और हायर सेकेंडरी (12वीं) मुख्य परीक्षा मार्च-अप्रैल 2026 के परिणाम घोषित किए। इस साल 12वीं का ओवरऑल रिजल्ट 71% रहा,जबकि 10वीं में 58.39% स्टूडेंट्स पास हुए। दोनों ही परीक्षाओं में छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए लड़कों से अधिक पास प्रतिशत दर्ज किया। 12वीं में लड़कियों का रिजल्ट 72.17% और लड़कों का 70.01% रहा। वहीं 10वीं में छात्राओं का पास प्रतिशत 59.82% और लड़कों का 57.43% दर्ज किया गया। 12वीं में कुल 40,256 स्टूडेंट्स

ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 38,683 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। इनमें कुल 24,823 स्टूडेंट्स पास हुए और ओवरऑल पास प्रतिशत 71% दर्ज किया गया। लड़कियों का रिजल्ट 72.17% रहा, जबकि लड़कों का पास प्रतिशत 70.01% दर्ज हुआ। यानी लड़कियां 2.16% की बढ़त के साथ आगे रहीं।

संपादकीय

असंभव नहीं पेपर लीक होने से रोकना

देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक नीट के प्रश्नपत्र लीक होने के कारण पूरी परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। इस पेपर लीक कांड ने लाखों युवाओं के सपनों और उनके अभिभावकों के भरोसे को तोड़कर रख दिया। नीट निरस्त होने से 22 लाख से अधिक छात्रों को यह परीक्षा फिर से देनी होगी। इन छात्रों और अभिभावकों के कष्टों का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। यह खेद की बात है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए एक बार फिर फेल हो गई। ध्यान रहे कि 2024 में भी नीट में गड़बड़ी के चलते कुछ केंद्रों की परीक्षा रद करके दोबारा करानी पड़ी थी।

यह केवल एक परीक्षा का पर्चा बाहर आना नहीं है,बल्कि देश की मेधा और भविष्य के साथ किया जाने वाला क्रूर मजाक है। क्या वास्तव में एक पारदर्शी परीक्षा प्रणाली विकसित करना असंभव है? पेपर लीक कांड के माफिया भली-भांति जानते हैं कि कुछ दिनों तक शोर मचेगा,जांच की घोषणाएं होंगी,धरना-प्रदर्शन होंगे और फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। इसी का फायदा उठाकर ऐसे अपराधी बेखौफ होकर अगली परीक्षा में सेंधमारी की तैयारियों में जुट जाते हैं। हमें कैटजैसी परीक्षाओं की ओर भी देखना चाहिए,जिसमें भी लाखों छात्र बैठते हैं,परंतु वहां पेपर लीक की घटनाएं लगभग शून्य हैं।

असल समस्या प्रबंधन की नहीं,बल्कि उस पूंजी की है जो मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के इर्द-गिर्द घूमती है। मेडिकल कालेजों विशेषकर निजी संस्थानों की सीटों में करोड़ों-अरबों का खेल चलता है। जब दांव पर इतना धन होता है, तो शक्तिशाली लोग और रसूखदार तंत्र सक्रिय हो जाते हैं। शायद यही कारण है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक को रोकने के लिए वह संजीदगी नहीं दिखाई जाती, जो दिखाई जानी चाहिए। प्रश्नपत्र तैयार करने, प्रिंट करने, फिर जिला स्तर के ट्रेजरी तक और वहां से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की वर्तमान व्यवस्था में इतनी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं शामिल हैं कि उसे फूलप्रूफ बना पाना बहुत मुश्किल है। धनबल या बाहुबल के माध्यम से इसमें से किसी भी कमजोर कड़ी को कभी भी तोड़ा जा सकता है।

यदि हम पेपर लीक की समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं,तो वर्तमान कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव करने होंगे। इसके लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया एक आदर्श उदाहरण हो सकती है। जिस तरह केंद्रीय बजट पेश होने से एक सप्ताह पहले वित्त मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों को बाहरी दुनिया से काटकर क्वारंटाइन कर दिया जाता है,वैसा ही माडल यहां भी अपनाया जाना चाहिए। परीक्षा से तीन-चार दिन पहले 10-12 विशेषज्ञों को एक गोपनीय और सुरक्षित स्थान पर एकत्र किया जाए। इनसे कम से कम 20 अलग-अलग प्रश्नपत्रों के सेट तैयार कराए जाएं, जिनमें सभी प्रश्नों के अंक एकसमान हों। मान लीजिए किसी परीक्षा में सौ प्रश्न पूछे जाने हैं तो 20 प्रश्नपत्रों के सेट के आधार पर 2,000 प्रश्नों का एक विशाल क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाए।

परीक्षा शुरू होने से मात्र दो-तीन घंटे पहले कंप्यूटर द्वारा रैंडम आधार पर इन 2,000 प्रश्नों में से सौ प्रश्नों का चयन किया जाए। इसकी पीडीएफ फाइल तुरंत तैयार कर पासवर्ड और डिजिटल सुरक्षा के साथ सभी केंद्रों को ईमेल कर दी जाए। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि परीक्षा शुरू होने के कुछ समय पहले तक किसी को भी,यहां तक कि परीक्षा कराने वाली संस्था के प्रमुख को भी नहीं पता होगा कि कौन से प्रश्न आने वाले हैं। जब जानकारी ही नहीं होगी, तो लीक होने की आशंका स्वतः शून्य हो जाएगी। यहां यह तर्क दिया जा सकता है कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर प्रिंटर खराब होने या बिजली चले जाने के कारण प्रश्नपत्रों की प्रिंटिंग में समस्या आ सकती है। इसका समाधान यह है कि हर परीक्षा केंद्र पर प्रिंटर और जेनरेटर का डबल नहीं, ट्रिपल बैकअप तैयार रखा जाए,ताकि एक के खराब होने पर दूसरे और दूसरे के खराब होने पर तीसरे से प्रश्नपत्र को तत्काल प्रिंट किया जा सके।

चूंकि कई मामलों में परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापक ही धांधली में शामिल पाए गए हैं, इसलिए कानून में सख्त प्रविधान की आवश्यकता है।

अंकों की अंधी दौड़ और खोता बचपन

डॉ. प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा

"अंकों की इस दौड़ में,बचपन हुआ उदास।
कंधों पर उम्मीद का,भारी पड़ा लिबास॥

भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा को हमेशा से सम्मान और प्रगति का माध्यम माना गया है। शिक्षा व्यक्ति को केवल ज्ञान ही नहीं देती,बल्कि उसे जीवन जीने की समझ,सामाजिक चेतना और बेहतर भविष्य की दिशा भी प्रदान करती है। किंतु समय के साथ शिक्षा का स्वरूप बदलता गया और आज स्थिति यह हो गई है कि शिक्षा का अर्थ केवल अधिक अंक लाना और प्रतियोगिता में आगे निकलना भर रह गया है। बच्चों का मूल्यांकन उनके व्यक्तित्व,व्यवहार, रचनात्मकता या संवेदनशीलता से नहीं, बल्कि उनकी मार्कशीट के प्रतिशत से किया जाने लगा है। परिणामस्वरूप बचपन दबाव, तनाव और अपेक्षाओं के बोझ तले कराह रहा है।

आज हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा कक्षा में प्रथम आए, सर्वोच्च अंक प्राप्त करे और समाज में प्रतिष्ठित पद हासिल करे। यह इच्छा स्वाभाविक है,क्योंकि हर अभिभावक अपने बच्चों का उज्ज्वल भविष्य चाहता है। समस्या तब शुरू होती है जब यह इच्छा अपेक्षा बन जाती है और अपेक्षा धीरे-धीरे दबाव में बदल जाती है। बच्चे की रुचि क्या है, उसकी क्षमता क्या है,उसे किस क्षेत्र में आनंद मिलता है–इन प्रश्नों पर कम ध्यान दिया जाता है। मुख्य चिंता केवल अंक और रैंक की रह जाती है।

वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ने बच्चों के जीवन को अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक बना दिया है। स्कूल की पढ़ाई के अतिरिक्त कोचिंग,ट्यूशन,ऑनलाइन क्लास और असाइनमेंट ने बच्चों के दिन का अधिकांश समय घेर लिया है। पहले बच्चे शाम को मैदानों में खेलते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे,दोस्तों के साथ हँसते-भागते थे,लेकिन आज उनका बचपन पुस्तकों और स्क्रीन के बीच कैद होकर रह गया है। खेल का मैदान अब मोबाइल की स्क्रीन में सिमट गया है और खुलकर हँसने की जगह परिणामों की चिंता ने ले ली है।

हर वर्ष परीक्षा परिणाम आने के बाद समाज का व्यवहार बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को और अधिक प्रभावित करता है। जिन बच्चों के अंक अधिक आते हैं,उन्हें समाज होनहार घोषित कर देता है,जबकि अपेक्षाकृत कम अंक पाने वाले बच्चे स्वयं को कमतर समझने लगते हैं। यह तुलना बच्चों के भीतर आत्महीनता पैदा करती है। कई बच्चे तनाव,अवसाद और भय से घिर जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कुछ बच्चे परीक्षा में असफलता के कारण आत्मघाती कदम तक उठा लेते हैं। यह स्थिति केवल शिक्षा व्यवस्था की नहीं,बल्कि पूरे समाज की विफलता का संकेत है।

आज बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव तुलना का पड़ रहा है। देखो, शर्मा जी का बेटा कितना पढ़ता है,उसके 98 प्रतिशत आए हैं,तुम्हारे क्यों नहीं? ऐसे वाक्य बच्चों के मन पर गहरी चोट करते हैं। तुलना कभी प्रेरणा नहीं बनती, बल्कि आत्मविश्वास को कमजोर करती है। हर बच्चा अपनी क्षमता, सोच और प्रतिभा में अलग होता है। कोई संगीत में उत्कृष्ट हो सकता है,कोई खेल में, कोई चित्रकला में और कोई लेखन में। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक सोच केवल डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी बनने को ही सफलता का पर्याय मानती है।

यह भी एक बड़ा प्रश्न है कि क्या केवल अधिक अंक प्राप्त कर लेना जीवन की सफलता की गारंटी है? इतिहास और वर्तमान दोनों इस बात के साक्षी हैं कि अनेक महान व्यक्तियों ने साधारण शैक्षिक उपलब्धियों के बावजूद असाधारण कार्य किए। सफलता केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं आती, बल्कि साहस,धैर्य,रचनात्मकता,संवेदनशीलता और मेहनत से आती है। यदि शिक्षा मनुष्य को अच्छा इंसान नहीं बना पा रही, तो वह अधूरी है।

आज के बच्चे तकनीकी रूप से बहुत तेज हैं,लेकिन भावनात्मक रूप से अकेले होते जा रहे हैं। माता-पिता दोनों के कामकाजी होने,संयुक्त परिवारों के टूटने और मोबाइल संस्कृति के बढ़ने से बच्चों को संवाद और भावनात्मक सहयोग कम मिल रहा है। वे अपनी परेशानियाँ किसी से खुलकर कह नहीं पाते। ऐसे में परीक्षा और भविष्य का दबाव उन्हें भीतर से तोड़ देता है। शिक्षा का वातावरण आनंददायक होने के बजाय भय का वातावरण बनता जा रहा है। कोचिंग संस्थानों की बढ़ती संस्कृति ने भी इस समस्या को गंभीर बनाया है। बड़े-बड़े विज्ञापनों में टॉपर्स के चेहरे दिखाकर बच्चों और अभिभावकों के मन में यह धारणा बना दी जाती है कि सफलता केवल कठिन प्रतिस्पर्धा और लगातार पढ़ाई से ही मिलेगी। बच्चों को मशीन की तरह तैयार किया जा रहा है। उनकी रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। शिक्षा अब सीखने की प्रक्रिया नहीं,बल्कि अंकों की फैक्ट्री बनती जा रही है।
सबसे दुखद स्थिति तब होती है जब बच्चे स्वयं को अपने माता-पिता के सपनों का बोझ समझने लगते हैं। वे डरते हैं कि यदि उनके अंक कम आए, तो वे परिवार को निराश कर देंगे। यह डर उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। कई बार माता-पिता अनजाने में बच्चों को यह महसूस करा देते हैं कि उनका प्यार भी अंकों पर निर्भर है। जबकि बच्चों को सबसे अधिक आवश्यकता बिना शर्त स्वीकार्यता और भावनात्मक सुरक्षा की होती है।
हमें यह समझना होगा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं है। शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए–मानवता, संवेदनशीलता, नैतिकता और आत्मविश्वास का विकास। यदि कोई बच्चा दूसरों की मदद करना सीखता है, अपने माता-पिता का सम्मान करता है, समाज के प्रति जिम्मेदार बनता है और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, तो वही सच्ची शिक्षा है।

बच्चों को अपनी रुचियों के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यदि किसी बच्चे को संगीत पसंद है, तो उसे संगीत में आगे बढ़ने दिया जाए। यदि किसी को खेल, अभिनय, लेखन, कला या किसी अन्य क्षेत्र में रुचि है, तो उसका सम्मान किया जाए। हर प्रतिभा महत्वपूर्ण है। समाज को यह समझना होगा कि दुनिया केवल डॉक्टर और इंजीनियरों से नहीं चलती,बल्कि कलाकारों,शिक्षकों, किसानों,लेखकों, वैज्ञानिकों,संगीतकारों और खिलाड़ियों से भी समृद्ध होती है।

अभिभावकों और शिक्षकों की जिम्मेदारी यहाँ सबसे अधिक है। बच्चों को डाँटने और डराने के बजाय उन्हें समझना और प्रेरित करना आवश्यक है। यदि बच्चा असफल होता है, तो उसे यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि असफलता अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। कई बार जीवन की सबसे बड़ी सफलताएँ असफलताओं से ही जन्म लेती हैं।

विद्यालयों को भी परीक्षा-केंद्रित शिक्षा से बाहर निकलकर व्यक्तित्व विकास,रचनात्मक गतिविधियों और नैतिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को केवल रटने के बजाय सोचने और समझने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के भीतर जिज्ञासा और आनंद जगाए,न कि भय और तनाव।

सरकार और समाज को भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होना होगा। स्कूलों में काउंसलिंग व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। माता-पिता को भी समय-समय पर यह समझाने की आवश्यकता है कि बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालना कितना हानिकारक हो सकता है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम शिक्षा और सफलता की परिभाषा बदलें। बच्चे को केवल अंक लाने वाली मशीन नहीं,बल्कि संवेदनशील और रचनात्मक इंसान के रूप में देखें। उसे यह महसूस कराएँ कि उसका मूल्य उसकी मार्कशीट से कहीं अधिक है।

यदि हम सच में आने वाली पीढ़ी को खुश, स्वस्थ और आत्मविश्वासी बनाना चाहते हैं, तो हमें अंकों की अंधी दौड़ से बाहर निकलना होगा। बच्चों को खेलने दीजिए, सपने देखने दीजिए, असफल होने दीजिए और फिर उठकर आगे बढ़ने दीजिए। क्योंकि जीवन केवल परीक्षा परिणामों का नाम नहीं, बल्कि अनुभवों, संघर्षों, संवेदनाओं और रिश्तों का सुंदर संगम है।
अंततः यही कहना उचित होगा कि–

अच्छे अंक नहीं,
बड़े और बड़ा बने इंसान।

दिल्ली दरबार पर भारी पड़ा जमीनी नेता

अजय कुमार,
लखनऊ,उत्तरप्रदेश

केरल में सतीशन क्यों बने कांग्रेस का चेहरा

केरल की राजनीति में इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदली,कांग्रेस की अंदरूनी ताकत का नक्शा भी बदल गया। दस वर्षों बाद सत्ता में लौटी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ने जब वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री चुना तो यह फैसला केवल एक व्यक्ति को कुर्सी सौंपने का नहीं था,बल्कि कांग्रेस के भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने वाला कदम बन गया। चुनाव नतीजे आने के बाद लगभग दस दिनों तक दिल्ली से तिरुवनंतपुरम तक जिस तरह की खींचतान चली,उसने साफ कर दिया था कि यह लड़ाई सिर्फ मुख्यमंत्री पद की नहीं, बल्कि कांग्रेस में'दिल्ली मॉडल बनाम जमीनी मॉडल'की थी। आखिरकार पार्टी ने संगठन महासचिव और राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाने वाले केसी वेणुगोपाल के बजाय उस नेता पर भरोसा जताया, जिसने पांच वर्षों तक विपक्ष में रहकर कांग्रेस को दोबारा खड़ा किया। 2026 के विधानसभा चुनाव में 140 सदस्यीय विधानसभा में यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। कांग्रेस ने अकेले 63 सीटें हासिल कीं, जबकि उसकी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतीं। एल डी एफ गठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया। 2021 में कांग्रेस नीत यूडीएफ को सिर्फ 41 सीटें मिली थीं और एलडीएफ 99 सीटों के साथ सत्ता में लौटा था। यानी पांच वर्षों में कांग्रेस ने 22 सीटों की सीधी बढ़त दर्ज की, जबकि वाम मोर्चा 64 सीटें खो बैठा। यही आंकड़े बताते हैं कि यह जीत किसी सामान्य सत्ता विरोधी लहर का परिणाम नहीं थी,बल्कि विपक्ष के नेता के रूप में वीडी सतीशन की बनाई राजनीतिक रणनीति का असर थी। दरअसल, 2021 की हार कांग्रेस के लिए केवल चुनावी पराजय नहीं थी, बल्कि संगठनात्मक संकट भी थी। पार्टी के भीतर वर्षों से चल रही 'ए ग्रूप' और 'आई ग्रूप' की राजनीति ने कार्यकर्ताओं को थका दिया था। ओमन चांडी और के. करुणाकरण के दौर से चली आ रही गुटबाजी ने कांग्रेस को जनता से दूर कर दिया था। ऐसे समय में राहुल गांधी ने रमेश चेन्निथला की जगह वीडी सतीशन को विपक्ष का नेता बनाया। उस समय यह फैसला जोखिम भरा माना गया, क्योंकि सतीशन के पास न दिल्ली की लॉबी थी और न ही संगठन पर वैसी पकड़, जैसी केसी वेणुगोपाल के पास मानी जाती थी। लेकिन पांच साल बाद वही फैसला कांग्रेस के पुनर्जीवन की सबसे बड़ी वजह बन गया। सतीशन ने विपक्ष का नेता बनने के बाद सबसे पहले कांग्रेस की चुनावी राजनीति की शैली बदली। उन्होंने साफ कहा कि टिकट वितरण में गुटीय वफादारी नहीं, बल्कि जीतने की क्षमता देखी जाएगी। इसका असर स्थानीय निकाय चुनावों में दिखाई दिया। दिसंबर 2025 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में यूडीएफ ने 941 पंचायतों में से 505 पर जीत हासिल की। 87 नगरपालिकाओं में से 54 यूडीएफ के खाते में गईं। 14 जिला पंचायतों में से 7 पर कब्जा हुआ, जबकि 6 में से 4 नगर निगमों में कांग्रेस गठबंधन को सफलता मिली। इन नतीजों ने पहली बार यह संकेत दिया कि एलडीएफ की पकड़ कमजोर हो रही है और कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है।

सतीशन की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उनकी 'डेटा आधारित राजनीति' रही। विधानसभा में उन्होंने सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं लगाए, बल्कि सरकारी आंकड़ों के जरिए पिनाराई विजयन सरकार को घेरा। केरल में बेरोजगारी दर, राज्य का बढ़ता कर्ज, सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार और युवाओं के पलायन जैसे मुद्दों को उन्होंने लगातार उठाया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, 2025 में केरल की शहरी बेरोजगारी दर 18 प्रतिशत के करीब पहुंच गई थी, जबकि युवाओं में यह आंकड़ा 30 प्रतिशत से अधिक था। पिछले पांच वर्षों में लगभग 18 लाख युवा रोजगार और शिक्षा के लिए राज्य से बाहर गए। सतीशन ने इन आंकड़ों को लगातार राजनीतिक मुद्दा बनाया और कांग्रेस को 'भविष्य की अर्थव्यवस्था'की भाषा बोलने वाली पार्टी के रूप में पेश किया। केरल की सामाजिक संरचना को समझे बिना इस फैसले को समझना मुश्किल है। राज्य की राजनीति में नायर,ईसाई और मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल दोनों नायर समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी राज्य में लगभग 14 से 15 प्रतिशत मानी जाती है। लेकिन फर्क यह रहा कि सतीशन लगातार नायर बहुल परवूर सीट से पांच बार चुनाव जीत चुके हैं। 2001,2006,2011, 2016 और 2021 में उन्होंने लगातार जीत दर्ज की। इससे उनकी जमीनी पकड़ मजबूत मानी जाती है। दूसरी ओर, वेणुगोपाल लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे और राज्य की सक्रिय राजनीति से उनकी दूरी बढ़ती गई।

कांग्रेस के लिए सबसे अहम बात यह थी कि सतीशन को अल्पसंख्यक समुदायों का भी व्यापक समर्थन हासिल था। केरल की लगभग 26 प्रतिशत आबादी मुस्लिम और करीब 18 प्रतिशत ईसाई है। यूडीएफ की सबसे बड़ी सहयोगी आईयूएमएल शुरू से सतीशन के पक्ष में थी। मुस्लिम लीग को यह आशंका थी कि अगर दिल्ली से कोई नेता मुख्यमंत्री बनकर आता है तो गठबंधन के भीतर संतुलन बिगड़ सकता है। चर्च समूहों के बीच भी सतीशन की छवि एक ऐसे नेता की रही,जो वैचारिक रूप से उदार हैं लेकिन धार्मिक तुष्टिकरण की खुली राजनीति नहीं करते। यही वजह रही कि कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें 'सर्वस्वीकार्य चेहरा' माना। केसी वेणुगोपाल की दावेदारी के सामने सबसे बड़ा संकट उनकी राजनीतिक स्थिति थी। वे लोकसभा सांसद हैं और पार्टी महासचिव भी। अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता तो पहले संसद सदस्यता छोड़नी पड़ती। इसके बाद किसी विधायक की सीट खाली कराकर उन्हें छह महीने के भीतर विधानसभा पहुंचाना पड़ता। यानी एक लोकसभा और एक विधानसभा उपचुनाव का अतिरिक्त जोखिम पैदा होता। कांग्रेस पहले ही जानती थी कि सत्ता में आने के बाद शुरुआती महीनों में किसी भी तरह की राजनीतिक अस्थिरता का संदेश नुकसानदेह साबित हो सकता है। यही कारण है कि अंतिम समय में हाईकमान ने 'कम जोखिम वाले विकल्प' पर भरोसा जताया।

इस फैसले का राष्ट्रीय राजनीतिक संदेश भी बड़ा है। कांग्रेस लंबे समय से इस आलोचना का सामना करती रही है कि पार्टी में फैसले सिर्फ दिल्ली दरबार के आधार पर होते हैं। लेकिन केरल में पार्टी ने पहली बार साफ संकेत दिया कि अब चुनाव जिताने वाले क्षेत्रीय नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सतीशन की ताजपोशी कांग्रेस के भीतर पीढ़ीगत बदलाव का भी प्रतीक मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल प्रमुख चेहरों केसी वेणुगोपाल, रमेश चेन्निथला और वीडी सतीशन में सतीशन को अपेक्षाकृत युवा और नई पीढ़ी के नेता के तौर पर देखा गया। उनका पूरा राजनीतिक अभियान 'नई कांग्रेस' की अवधारणा पर आधारित था। भाजपा के बढ़ते प्रभाव को रोकना भी इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण रहा। पिछले कुछ वर्षों में भाजपा ने केरल में हिंदू वोटों,खासकर नायर समुदाय के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश की। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत 16 प्रतिशत के करीब पहुंच गया था। कांग्रेस समझती थी कि उसे ऐसा चेहरा चाहिए, जो हिंदू समाज में स्वीकार्य हो लेकिन अल्पसंख्यकों के बीच भी भरोसेमंद बना रहे। सतीशन इस राजनीतिक संतुलन में फिट बैठते हैं। उनकी छवि आक्रामक सांप्रदायिक राजनीति से दूर लेकिन सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई मानी जाती है। अब सबसे बड़ी चुनौती वादों को जमीन पर उतारने की होगी। केरल इस समय लगभग 4 लाख करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। राज्य में निजी निवेश की रफ्तार धीमी है और युवाओं का पलायन लगातार बढ़ रहा है। सतीशन ने चुनाव के दौरान 'ग्लोबल जॉब नेटवर्क', शिक्षा सुधार और स्टार्टअप अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का वादा किया था। अगर वे इन मोर्चों पर ठोस परिणाम देते हैं तो कांग्रेस सिर्फ केरल में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नया राजनीतिक मॉडल पेश कर सकती है। वीडी सतीशन की जीत ने यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस अब केवल हाईकमान आधारित राजनीति के भरोसे नहीं चलना चाहती। केरल में पार्टी ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि जनता और कार्यकर्ताओं के बीच स्वीकार्यता रखने वाला नेता ही सबसे बड़ा राजनीतिक निवेश होता है। यही कारण है कि इस बार दिल्ली की ताकत पर जमीन की हकीकत भारी पड़ गई।

एक दिन

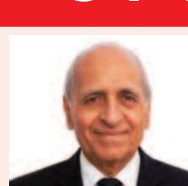

प्रोफेसर
शाम लाल
कौशल
रोहतक,
हरियाणा

आज बेशक अकड़ अकड़ कर चल रहे हैं लेकिन
एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमसे चला भी नहीं जाएगा!
आज बेशक ऊंचे ऊंचे मकान बनाकर अकड़ दिखला रहे हैं
लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा सब धराशायी हो जाएगा!
आजकल बेशक हम मस्त जवानी की कितनी अकड़ दिखाएं
लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमें बुढ़ापा हो जाएगा
बेशक आज किसी वजह से लोग झुक झुक कर सलाम करते हो
लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग बात भी नहीं करेंगे!
बेशक आज हमारे पास ऊंचा ओहदा है और सब हमसे डरते हैं
लेकिन जब यह ओहदा नहीं रहेगा हमारी बड़ी दुर्गति होगी।
आज बेशक हमारे व्यापार में चार चांद लग रहे हो और सब
चारों तरफ मशहूर हैं लेकिन एक दिन सब कुछ चौपट हो जाएगा।
बेशक आज हमारे परिवार में खूब रौनक है सब मिलकर रहते हैं
वक्त आने पर स्वार्थ वश सब लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे।
आज जिन स्थानों पर किसी न किसी कारण मेले लग रहे हैं
एक दिन ऐसा भी हो जाएगा जब यहां बिल्कुल सुनसान होगी।
बस वक्त के बदलने से हालात बदलते हैं आदमी भी बदल जाते हैं
जिस तरह का वक्त हो मस्त होकर बेफिक्री से काट लेना चाहिए।

सवालों के घेरे में व्यवस्था

संजय
एम
तराणेकर
इन्दौर
मध्यप्रदेश

नीट का पेपर जब लीक हुआ,
हरेक सपना जैसे ध्वस्त हुआ।
अथक मेहनत की रातें रो पड़ीं,
ईमान की राहें जैसे खोई पड़ीं।
जिस शिक्षा पर था देश टिका,
वहीं भरोसे का एक दीप बुझा।
कागज़के कुछ टुकड़ों ने फिर,
लाखों का भविष्य उजाड़ दिया।
यूं अब सरकारों की चौखट पर,
जनता का प्रश्नचिन्ह खड़ा होगा।
इस युग कैसे गोपनीय दीवारों से,
प्रश्न-पत्र बाहर फैला पड़ा होगा?

बच्चे दिन-रात एक किये हुवे थे,
आशा-अपेक्षा लेकर आगे बढ़े थे।
क्यों उनकी आँखों के सपनों पर,
स्वार्थियों के काले रंग चढ़े हुए थे?
सीबीआई की कठोर जांच चले,
सच्चाई के पहरे में हर द्वार खुले।
इसके दोषी चाहे जितने बड़े हों,
न्याय के आगे उनका शीश झुके।
शिक्षा मंदिर कहलाता है देश का,
सबको इसका सम्मान बचाना है।
मेहनत करने वाले हरेक मन को,
फिर विश्वास का दीप दिलाना है।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

साख पर बट्टा

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

उस दिन घर के स्टोर-रूम के सबसे अंधेरे कोने में, जहाँ मकड़ियों ने अपनी नई रियासत बसाई थी, एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। घर की नई बहू ने कबाड़ साफ करते हुए एक भारी, आयताकार पत्थर को पैर से ठेल दिया। वह पत्थर, जो कभी इस घर की रसोई का भीष्म पितामह था, जिस पर मेरी दादी ने अपनी पूरी जवानी घिस दी थी और जिसकी रगड़ से निकली खुशबू मोहल्ले के आवारा कुत्तों की भूख भी जगा देती थी, आज अपनी ही औलादों के घर में अछूत हो गया था। सिलबट्टा मरता नहीं है, वह बस चुप हो जाता है। उसकी यह चुप्पी किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की संवेदनाओं से साक्षात्कार करने लगती है। आज के इस ग्लास-फिनिश वाले ज़माने में, जहाँ रिश्ते भी इंस्टेंट नूडल्स की तरह दो मिनट में बनते और बिगड़ते हैं, वह सिलबट्टा उस पुराने, वफादार मज़दूर की तरह कोप भवन में पड़ा है, जिसे जबरन वीआरएस के बाद घर के बाहर वाले कमरे में खटिया दे दी गई हो। सिलबट्टे का जाना दरअसल हमारे घर की ममता का अंत है। हमें याद है, माँ जब उस पर लाल मिर्च और लहसुन का इंसाफ करती थी, तो पत्थर और बट्टे की जो जुगलबंदी होती थी, वह किसी रूहानी संगीत से कम नहीं थी। वह सूँ-सूँ की आवाज़... वह पत्थर का पत्थर से टकराना... वह केवल मसाला नहीं पिस रहा होता था, बल्कि माँ अपने दिन भर की सारी थकान, सारा गुस्सा और सारा प्यार उस सिल पर उंडेल देती थी। सारा गुस्सा सिलबट्टे पर उंडेल देने से घरवालों से लड़ाई-झगड़ा करने का मन ही नहीं होता था। सिलबट्टे से चटनी नहीं बनती थी, वह माँ के हाथ का रक्तचाप होता था जो हमारे पेट में जाकर हमें सुकून देता था। आज की मिक्सी तो कैंसर की मशीन है। वह चलती है तो ऐसा लगता है जैसे घर में कोई इलेक्ट्रिक कटर चल रहा हो। इस आवाज़ का दिमाग पर भी असर होता है। इस आवाज़ के चलते छोटी-छोटी बातें कब पहाड़ बन कर अनबन कर दें, पता ही नहीं चलता है। मिक्सी मसालों को पीसती नहीं है, उनके अरमानों का कत्ल कर देती है। मिक्सी के ब्लेड मसालों को इतनी बेरहमी से काटते हैं कि बेचारे धनिये का डीएनए बदल जाता है। स्वाद तो उस रगड़ में था, उस घर्षण में था, जो अब केवल इतिहास की किताबों में मिलेगा। दरअसल सिलबट्टा वह बुज़ुर्ग था, जिसकी उपस्थिति मात्र से रसोई में एक अनुशासन रहता था। जब सुबह-सुबह उस पर लयबद्ध तान छिड़ती थी, तो ऐसा लगता था जैसे प्रकृति स्वयं कोई राग दरबारी गा रही हो। वह सिल को टांकने (छेदने) वाला शिल्पकार जब साल भर बाद आता था, तो वह हमारे लिए किसी सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाले इंजीनियर से बड़ा होता था।

मॉन्टफोर्ट स्कूल का 12 वीं बोर्ड परिणाम शत-प्रतिशत
शीना मेहता ने सरगुजा जिले में किया टॉप....

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 14 मई 2026 (घटती-घटना)।

मॉन्टफोर्ट स्कूल ने एक बार फिर शैक्षणिक उत्कृष्टता का परिचय देते हुए सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा में शत-प्रतिशत परिणाम हासिल किया है। विद्यालय की छात्रा शीना मेहता ने 97.2 प्रतिशत अंक अर्जित कर न केवल स्कूल बल्कि पूरे सरगुजा जिले का नाम रोशन किया है। शीना ने जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय परिवार को गौरवान्वित किया। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद विद्यालय परिसर में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। छात्र-छात्राओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी सफलता का जश्न मनाया। अभिभावकों एवं शिक्षकों ने भी विद्यार्थियों की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की।

इन विद्यार्थियों ने भी किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

विद्यालय के अन्य मेधावी विद्यार्थियों में दिव्या तिग्गा एवं आयुष ठाकुर ने 92.4-92.4 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वहीं ऋषिकेश संदीप ने 88 प्रतिशत, अनुराग पाण्डेय एवं कनकश्री ने 87-87 प्रतिशत, वंशिका सिंह ने 86 प्रतिशत, पवन प्रकाश ने 85.5 प्रतिशत, प्रेसी कुर्रे ने 85.4 प्रतिशत तथा लवन्या सिंह ने 85 प्रतिशत अंक अर्जित कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। विद्यालय प्रबंधन के अनुसार इस वर्ष विद्यार्थियों ने सभी संकायों में बेहतर प्रदर्शन किया है। शिक्षकों की सतत निगरानी, नियमित टेस्ट एवं अनुशासित अध्ययन व्यवस्था का सकारात्मक परिणाम परीक्षा में देखने को मिला।

मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन का मिला परिणाम : विद्यालय के प्राचार्य ब्रदर सेवक गेब्रियल ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग का संयुक्त परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि निरंतर मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि मॉन्टफोर्ट स्कूल हमेशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देता रहा है। विद्यालय विद्यार्थियों को केवल परीक्षा तक सीमित न रखकर उनके सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान देता है।

अभिभावकों में भी खुशी का माहौल : बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन के बाद अभिभावकों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। कई अभिभावकों ने विद्यालय के शिक्षकों एवं प्रबंधन की सराहना करते हुए कहा कि स्कूल द्वारा बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, जिसका परिणाम हर वर्ष उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के रूप में सामने आता है। विद्यालय प्रबंधन ने सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा सौम्या दुबे ने 92.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर बढ़ाया मान

अंबिकापुर के होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा सौम्या दुबे ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 92.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय एवं परिवार का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से परिजनों, शिक्षकों एवं शुभचिंतकों में खुशी का माहौल है। सौम्या दुबे बचपन से ही पढ़ाई में प्रतिभाशाली रही हैं। उन्होंने केजी से लेकर दसवीं कक्षा तक लगातार 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वियानी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई। सौम्या के पिता विनय कुमार दुबे उदयपुर में निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी हैं। सामान्य परिवार से आने वाली सौम्या ने कठिन मेहनत, अनुशासन और निरंतर अध्ययन के बल पर यह सफलता प्राप्त की है। पढ़ाई के अलावा सौम्या को पुस्तकें पढ़ने एवं यात्रा करने का विशेष शौक है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों एवं विद्यालय के सहयोग को दिया है। विद्यालय परिवार ने सौम्या की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

जवाहर नवोदय विद्यालय खलिबा का 12वीं परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत, विद्यार्थियों ने बढ़ाया गौरव

पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय ख़लिबा अंबिकापुर का इस वर्ष कक्षा 12 वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम अत्यंत उत्कृष्ट एवं गौरवपूर्ण रहा। विद्यालय के कुल 50 विद्यार्थियों ने वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षा में हिस्सा लिया, जिनमें सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर विद्यालय को शत-प्रतिशत परिणाम दिलाने में सफल रहे। विद्यालय के छात्र राहुल कुमार ने 96.6 प्रतिशत अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं ईशांत जांगड़े ने 95 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। छात्रा श्वेता रतिया ने 94.2 प्रतिशत अंक अर्जित कर तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय प्राचार्य एवं समस्त विद्यालय परिवार ने सभी सफल विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दी हैं। विद्यालय प्रशासन ने इस सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन तथा अभिभावकों के निरंतर सहयोग को दिया है। विद्यालय के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम से विद्यार्थियों एवं अभिभावकों में हर्ष का माहौल है।

ऑटो चालक से डकैती का खुलासा
24 घंटे के भीतर 2 आरोपी गिरफ्तार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 14 मई 2026 (घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना क्षेत्र में ऑटो चालक से डकैती करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं, जो अंबिकापुर में रहकर वारदात को अंजाम दे रहे थे।

शादी समारोह से लौट रहे ऑटो चालक को बनाया निशाना : मामले में प्रार्थी धर्मेन्द्र यादव निवासी कल्याणपुर थाना जयनगर जिला सूरजपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 12 मई 2026 की रात करीब 12 बजे कोलडीहा में आयोजित शादी समारोह से ऑटो लेकर अपने घर कल्याणपुर लौट रहा था। रात करीब 12:40 बजे ग्राम घंधरी गेरवानी नाला के पास पहुंचने पर पीछे से 6 पल्सर मोटरसाइकल में सवार 10 से 12 युवक पहुंचे। आरोपियों ने ऑटो के सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर उसे रोक लिया और गन दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसका एकवा कंपनी का मोबाइल फोन लूट लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए।

सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को मिला सुराग : प्रार्थी की शिकायत पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 274/2026 धारा 126(2), 310(2) बीएनएस एवं 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल अंबिकापुर और थाना गांधीनगर की संयुक्त टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने घटना स्थल के आसपास पूछताछ करने के साथ ही प्रतापपुर-अंबिकापुर मार्ग में लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज के बारीकी से परीक्षण के दौरान कुछ युवक घटना के बाद मोटरसाइकिल से जाते दिखाई दिए, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान वैभव मिश्रा और लवकुश कुमार के रूप में की।

उत्तर प्रदेश निवासी निकले आरोपी : पुलिस ने आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर वैभव मिश्रा (20 वर्ष) निवासी कुड़वार जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश लवकुश कुमार (24 वर्ष) निवासी कुड़वार जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश को हिरासत में लिया। दोनों वर्तमान में राजा गैस गोदाम के पास अंबिकापुर में रह रहे थे। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।

पेट्रोल पम्प मैनेजर से लूट का खुलासा..
4 आरोपियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 14 मई 2026 (घटती-घटना)।

दरिमा थाना क्षेत्र में पेट्रोल पम्प के मैनेजर से लूटपाट करने वाले 4 आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है, जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक को बाल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दो वाहन भी जब्त किए हैं।

पेट्रोल पम्प से हिसाब कर लौट रहा था मैनेजर : मामले में प्रार्थी शिवचंद वर्मा, निवासी गांधीनगर अंबिकापुर ने 7 मई 2026 को थाना दरिमा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थी के अनुसार वह कुम्हारता-नचाई स्थित वेदिका पेट्रोल पम्प से हिसाब कर करीब 61 हजार 670 रुपए नगद लेकर अंबिकापुर लौट रहा था। इसी दौरान नचाई चौक के पास दो मोटरसाइकिलों में सवार 4 युवक चेहरा ढककर पहुंचे और रास्ता रोक लिया। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी तथा नगदी रकम, मोबाइल फोन, हिसाब की डायरी और मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गए।

सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों तक पहुंची पुलिस : घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना दरिमा में अपराध क्रमांक 108/2026 धारा 309(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। आरोपियों की तलाश के लिए विशेष पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस ने दरिमा से गांधीनगर तक लगे सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। फुटेज में मिले हुलिये के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान दुर्गेश उर्फ यश ईमालिया, आकाश झारिया, निशांत नगेसिया और एक अन्य के रूप में की।

नौकरी से निकाले जाने की रंजिश में रची लूट की साजिश : पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी दुर्गेश उर्फ यश ईमालिया ने खुलासा किया कि वह पहले वेदिका पेट्रोल पम्प में काम करता था। उसने अपनी शादी के लिए पेट्रोल पम्प से बिना अनुमति 30 हजार रुपए ले लिए थे। इसकी जानकारी मिलने पर पम्प संचालक ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। इसी रंजिश के चलते उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पेट्रोल पम्प मैनेजर से लूट की योजना बनाई और वारदात को अंजाम दिया।

तीन आरोपी गिरफ्तार, वाहन जब्त : पुलिस ने मामले में दुर्गेश उर्फ यश ईमालिया (22 वर्ष), आकाश झारिया (20 वर्ष), निशांत नगेसिया (20 वर्ष) को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सभी ने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक CG15DX5401 तथा एक्टिवा स्कूटी क्रमांक CG15EH7025 जब्त की गई है।

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका : पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी दरिमा निरीक्षक राजेश खलखो, थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रवीण द्विवेदी, साइबर सेल अंबिकापुर की टीम सहित सहायक उप निरीक्षक अजीत कुमार मिश्रा, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, विकास सिन्हा, जयदीप सिंह तथा अन्य पुलिसकर्मियों की सक्रिय भूमिका रही।

जीएच रायसोनी मेमोरियल ऑल इंडिया ओपन फिडे रेटेड रैपिड शतरंज प्रतियोगिता 30 व 31 मई को

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 14 मई 2026 (घटती-घटना)।

शतरंज संघ सरगुजा द्वारा 30 एवं 31 मई को जीएच रायसोनी मेमोरियल ऑल इंडिया ओपन फिडे रेटेड रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर, अंबिकापुर में होगा। शतरंज संघ द्वारा राष्ट्रीय स्तार पर पहली बार प्रतियोगिता कराई जा रही है। प्रतियोगिता 9 चक्रों में होगी, जिसमें सभी वर्गों के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। प्रतियोगिता के लिए प्रवेश शुल्क 250 रुपये रखा गया है। सभी वर्गों के लिए ट्राफी एवं प्राइज मनी अलग-अलग रखी गई है। ओपन वर्ग में ट्राफी- मेडल के साथ प्रभम पुस्कार 11 हजार रुपये, द्वितीय 7 हजार, तृतीय 5 हजार, चतुर्थ 4 हजार एवं पंचम पुरस्कार 3 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। इसके अलावा छठवें से दसवां तक 1 हजार एवं ग्यारहवें से बीसवां तक 500 रुपए पुरस्कार राशि दिए जाएंगे। इसके अलावा अंडर-7, अंडर-9, अंडर-11, अंडर-13 और अंडर-15 वर्ग के विजेता बालक-बालिकाओं को बेस्ट वैटरन, बेस्ट अनरेटेड, बेस्ट फिमल (15प्लस), बेस्ट रेटिंग (1400-1550) एवं बेस्ट सरगुजा के पुरूष एवं महिला को भी प्राइज मनी एवं ट्राफी दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में बिना विलंब शुल्क के भाग लेने की अतिम तिथि 23 मई की शाम 5 बजे तक है। इसके बाद 250 रुपए विलंब शुल्क के साथ 25 मई की शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। नए खिलाडियों को सीजीएससीए रजिस्ट्रेशन शुल्क 150 रुपए एवं एआईसीएफ का रजिस्ट्रेशन शुल्क 300 भी जमा करना होगा। प्रतियोगिता के संबंध में विस्तृत जानकारी चीफ अंतर्राष्ट्रीय आर्बिटर अनीस अंसारी मोबाइल नंबर 6261980179 एवं नेशनल आर्बिटर प्रदीप मंडल मोबाइल नंबर 9981598072 से प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त जानकारी शतरंज संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा ने दी।

नशे में धुत्त व्यक्ति ने सब्जी व्यापारी पर किया हमला, मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 14 मई 2026 (घटती-घटना)।

जनकपुर साप्ताहिक बाजार के पास बुधवार को शराब के नशे में धूत एक व्यक्ति ने टांगी से बाइक सवार सब्जी व्यापारी के गर्दन पर हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रामप्रसाद उम्र 56 वर्ष रघुनाथनगर का रहने वाला था। वह साप्ताहिक बाजारों में जाकर सब्जी बेचने का काम करता था। बुधवार को वह जनकपुर साप्ताहिक बाजार में सब्जी बेचने गया था। वह बाइक से और सब्जी लाने जा रहा था। तभी जनकपुर साप्ताहिक बाजार के पास नशे में धूत बंधु सिंह ने टांगी से उसके गर्दन पर अचानक हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया।

मेडिकल कॉलेज रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई...मरीजों को राहत की उम्मीद
जाम और अव्यवस्था से परेशान थे लोग, शिकायत के बाद प्रशासन ने दिखाई सख्ती

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 14 मई 2026 (घटती-घटना)।

शहर के सबसे व्यस्त और संवेदनशील मार्गों में शामिल मेडिकल कॉलेज अस्पताल रोड पर आखिरकार प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। लंबे समय से सड़क किनारे अवैध रूप से लग रहे ठेले-गुमटियों और दुकानों के बाहर फैले सामान के कारण यहां लगातार जाम की स्थिति बन रही थी। मरीजों, एंबुलेंस चालकों और आम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही थी। गुरुवार को प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया। कार्रवाई के दौरान दर्जनों ठेले-गुमटियों को हटाया गया, वहीं कई दुकानों के बाहर रखे सामान को भी जब्त किया गया। प्रशासन की टीम जेसीबी और निगम अमले के साथ मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे अव्यवस्थित तरीके से रखे सामान को हटाने के साथ दुकानदारों को कड़ी चेतावनी भी दी गई। मेडिकल कॉलेज अस्पताल रोड शहर का प्रमुख मार्ग माना जाता है।

इसी रास्ते से बड़ी संख्या में मरीज, एंबुलेंस और मेडिकल कॉलेज आने-जाने वाले लोग गुजरते हैं। लेकिन लंबे समय से सड़क किनारे ठेले-गुमटियों के बढ़ते कब्जे के कारण यहां आए दिन जाम लग रहा था। कई बार एंबुलेंस तक को रास्ता निकालने में परेशानी होती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम के समय सड़क की स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती थी।

बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने भी प्रशासन से शिकायत की थी कि सड़क पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण से अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसके बाद प्रशासन ने नगर निगम के साथ संयुक्त अभियान चलाकर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों और ठेला संचालकों को सड़क पर सामान नहीं फैलाने की समझाइश दी। निगम प्रशासन ने साफ किया कि जिन ठेला संचालकों को हटाया गया है, उन्हें तय स्थानों पर ही दुकान लगाने की अनुमति होगी। सड़क और अस्पताल मार्ग पर दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद लोगों ने राहत की उम्मीद जताई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि नियमित निगरानी होती रही तो मेडिकल कॉलेज रोड पर जाम और अव्यवस्था की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है।

20 मई को बंद रहेंगी दवा दुकानें...
सरगुजा औषधि विक्रेता संघ ने सौंपा ज्ञापन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 14 मई 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा औषधि विक्रेता संघ द्वारा 20 मई 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद को लेकर जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों को ज्ञापन सौंपा गया। संघ के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों से अवगत कराया। संघ के अध्यक्ष अमित 'मिंटू' अग्रवाल ने बताया कि यह बंद ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर किया जा रहा है। यह संगठन देशभर के 12.50 लाख से अधिक दवा विक्रेताओं एवं वितरकों का प्रतिनिधित्व करता है। ज्ञापन सरगुजा कलेक्टर श्री अजित बसंत, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अंबिकापुर इकाई के अध्यक्ष डॉ. अजय तिर्की तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन के एडीसी श्री किशोर ठाकुर की अनुपस्थिति में ड्रग इंस्पेक्टर श्री अनिल पैंकरा एवं श्री अमरेश तिर्की को सौंपा गया। संघ के उपाध्यक्ष नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि 20 मई का बंद केवल व्यापारिक मुद्दा नहीं है, बल्कि जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने सभी होलसेलर एवं रिटेलर केमिस्ट साथियों, प्रशासन और आम नागरिकों से बंद को समर्थन देने की अपील की।

ये हैं प्रमुख मांगें : ज्ञापन में अवैध ई-फार्मेसी संचालन पर तत्काल रोक लगाने, बड़े कॉर्पोरेट समूहों द्वारा अत्यधिक छूट देकर दवा बिक्री पर नियंत्रण लगाने तथा कोविड-19 काल में जारी अधिसूचना क्रमांक 220 को वापस लेने की मांग की गई है। इस दौरान संघ के सचिव अजय पाठक, कोषाध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष नरेंद्र भानु विश्वकर्मा, सुमित अग्रवाल, लोकेश सोनी, विक्की मुस्तफा रजा खान सहित संघ के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

पीएम की अपील का असर : सरगुजा के मंत्रियों ने बदली सरकारी सियासत की तस्वीर
प्रोटोकॉल और काफिलों से दूरी बनाकर सादगी का संदेश, प्रशासनिक खर्च घटाने पर भी जोर

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 14 मई 2026 (घटती-घटना)।

प्रदेश की राजनीति में अक्सर लंबे काफिले, पायलट वाहन और भारी सुरक्षा व्यवस्था चर्चा का विषय बनते रहे हैं, लेकिन अब सरगुजा संभाग के तीन मंत्रियों ने इस पर अलग पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ईंधन संरक्षण और सादगीपूर्ण जीवनशैली अपनाने की अपील के बाद संभाग के मंत्रियों ने अपने प्रोटोकॉल वाहनों के उपयोग को सीमित करने का फैसला लिया है। इस निर्णय को प्रशासनिक सादगी और सरकारी खर्च में कटौती की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल तथा वरिष्ठ मंत्री रामविचार नेताम ने स्पष्ट किया है कि अब सामान्य परिस्थितियों में पायलट वाहन, फॉलो गाड़ी और अतिरिक्त प्रोटोकॉल वाहनों का उपयोग नहीं किया जाएगा। केवल सुरक्षा संबंधी विशेष परिस्थितियों या जरूरी सरकारी कार्यक्रमों में ही इन वाहनों का इस्तेमाल होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला केवल ईंधन बचत तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता के बीच सादगीपूर्ण छवि बनाने का प्रयास भी है। आमतौर पर मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के बड़े काफिलों को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिलती है। ऐसे में यह पहल आम लोगों के बीच सकारात्मक संदेश देने वाली मानी जा रही है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभागीय अधिकारियों को भी अनावश्यक सरकारी वाहनों के उपयोग से बचने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक विषय नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रहित से जुड़ी जिम्मेदारी है। सरकारी संसाधनों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही होना चाहिए। वहीं पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल पहले भी अपनी सादगी को लेकर चर्चा में रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार वे कई बार अपने गृह क्षेत्र में स्कूटी से घूमते नजर आए हैं। अब उनके इस निर्णय को उसी सादगीपूर्ण कार्यशैली का विस्तार माना जा रहा है। मंत्री रामविचार नेताम ने भी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से जरूरत के अनुसार ही वाहनों के उपयोग की अपील की है।

इसका असर स्थानीय स्तर पर भी दिखने लगा है। कई जनप्रतिनिधि अब छोटी दूरी के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग करते दिखाई दे रहे हैं। प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि यदि यह व्यवस्था लंबे समय तक लागू रहती है तो इससे सरकारी खर्च में कमी आने के साथ-साथ ईंधन की भी बचत होगी।

केल्हारी वन विभाग कार्यालय का कांग्रेस ने किया घेराव

भालू पीड़ितों को मुआवजा,तेंदूपत्ता भुगतान और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गरजा कांग्रेस का धरना

-संवाददाता-
एमसीबी/ मनेंद्रगढ़,14 मई 2026
(घटती-घटना)।

कांग्रेस द्वारा मनेंद्रगढ़ क्षेत्र के केल्हारी वन परिक्षेत्र कार्यालय का घेराव कर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं,कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने वन विभाग पर भ्रष्टाचार, तेंदूपत्ता भुगतान में देरी,भालू हमले के पीड़ितों की अनदेखी और ग्रामीणों के शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए, धरना प्रदर्शन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण मनेंद्रगढ़ के नेतृत्व में आयोजित किया गया,जहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया,प्रदर्शन के दौरान वन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और ग्रामीणों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया।

महुआ पेड़ और ट्री गार्ड में हुआ भ्रष्टाचार- जिला कांग्रेस कमेटी एमसीबी के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि साठ हजार महुआ पेड़ लगाने के नाम पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है,उन्होंने कहा कि ट्री गार्ड निर्माण में भी भारी अनियमितताएं सामने आई हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए,उन्होंने भालू हमले में घायल ग्रामीण को पर्याप्त सहायता राशि नहीं मिलने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जहां पीड़ित को 50 हजार रुपये मिलना चाहिए था, वहां मात्र 1500 रुपये देकर औपचारिकता निभाई गई। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों पर भाजपा समर्थित मानसिकता से काम करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि तेंदूपत्ता संग्राहकों का भुगतान शीघ्र नहीं हुआ तो कांग्रेस मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाकर विरोध दर्ज कराएगी।

ग्रामीणों की चिंता छोड़ भ्रष्टाचार में व्यस्त विभाग-

ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण मनेंद्रगढ़ के अध्यक्ष रामनरेश पटेल ने कहा कि भालू हमले से प्रभावित परिवारों को राहत देने के बजाय वन विभाग महुआ वृक्षारोपण और ट्री गार्ड के नाम पर भ्रष्टाचार में उलझा हुआ है, उन्होंने कहा कि ग्रामीण लगातार वन्यजीव हमलों और आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग संवेदनशीलता दिखाने के बजाय कागजी योजनाओं में व्यस्त दिखाई देता है।

गरीबों की झोपड़ी टूट रही,भुगतान नहीं मिल रहा- पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने कहा कि गरीब और ग्रामीण जनता के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासनकाल में आम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, उन्होंने कहा कि वन विभाग एक ओर गरीबों की झोपड़ियां तोड़ने में सक्रिय है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं और अधिकार देने में विफल साबित हो रहा है, उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों के लंबित भुगतान को तत्काल जारी करने और भालू पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग करते हुए कहा कि ग्रामीणों को छोटी-छोटी सहायता राशि के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, मजदूरों और तेंदूपत्ता संग्राहकों को समय पर भुगतान नहीं मिलने से ग्रामीण परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं,उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगें जल्द पूरी नहीं हुईं तो कांग्रेस इससे भी बड़ा आंदोलन करेगी।

बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता और ग्रामीण

धरना प्रदर्शन में जिला उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी, महिला जिला अध्यक्ष ग्रामीण निर्मला चतुर्वेदी,जिला महामंत्री रफीक मेमन,ओम प्रकाश गुप्ता,आदिवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष अमोल सिंह,जिला प्रवक्ता भावेश जैन,मजदूर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मकसूद आलम,महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नीलिमा शामल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी,कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे, धरना स्थल पर लगातार नारेबाजी होती रही और ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ अपनी नाराजगी खुलकर व्यक्त की, प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।

वनरक्षक से धोखाधड़ी का आरोपी कथित पत्रकार गिरफ्तार

स्कॉर्पियो खरीदकर नहीं किया पूरा भुगतान,रकम मांगने पर जातिसूचक गालियां देने का आरोप

-सुदामा राजवाड़े-
राजपुर,14 मई 2026
(घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में वनरक्षक से धोखाधड़ी, जातिसूचक गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप में कथित पत्रकार संतोष सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं सहित एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मामला महुआडांड़ बासेन निवासी एवं वन परिक्षेत्र राजपुर के नरसिंहपुर बीट में पदस्थ वनरक्षक राकेश प्रसाद लकड़ा की शिकायत पर दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता के अनुसार वर्ष 2023 में उनकी स्कॉर्पियो वाहन क्रमांक CG 15 CW 1510 का सौदा संतोष सोनी के साथ 4 लाख 25 हजार रुपए में हुआ था। आरोप है कि आरोपी ने वाहन लेने के बाद पूरी राशि का भुगतान नहीं किया और लगातार टालमटोल करता रहा।

चेक दिया,फिर कहा खाते में पैसा नहीं : शिकायत में बताया गया है कि आरोपी द्वारा करीब 2 लाख रुपए किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से दिए गए थे,जबकि शेष 2 लाख 21 हजार रुपए के भुगतान के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया गया। करीब तीन माह बाद जब शिकायतकर्ता ने चेक बैंक में लगाने की बात कही, तब आरोपी ने खुद खाते में रकम नहीं होने की जानकारी देते हुए चेक जमा नहीं करने का आग्रह किया और जल्द भुगतान करने का आश्वासन दिया। इसके बाद भी वह लगातार भुगतान टालता रहा।

पैसे मांगने पहुंचे तो गाली-गलौज और धमकी

शिकायतकर्ता के मुताबिक 12 मई को वह विजय तिर्की के साथ राजपुर स्थित आरोपी की दुकान पर भुगतान की बात करने पहुंचे थे। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने जातिसूचक गालियां देते हुए अभद्र व्यवहार किया और पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, 'जहां जाना है जाओ,देख लूंगा' कहते हुए धमकी देकर वहां से भगा दिया गया। इसके बाद आरोपी ने फोन उठाना भी बंद कर दिया।

एससी-एसटी एक्ट सहित गंभीर धाराओं में केस

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के निर्देशन में राजपुर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 सहित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

पत्रकारिता की आड़ में संरक्षण मिलने की चर्चा : क्षेत्र में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि कुछ समय पहले एक बड़े समाचार पत्र द्वारा संतोष सोनी को राजपुर क्षेत्र का संवाददाता बनाया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि मीडिया संस्थानों को नियुक्ति से पहले संबंधित व्यक्ति की सामाजिक और कानूनी पृष्ठभूमि की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। लोगों का यह भी आरोप है कि आरोपी को कुछ प्रभावशाली लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते कई मामले लंबित होने के बावजूद कार्रवाई अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

कई जिलों में लंबित बताए जा रहे मामले : जानकारों के अनुसार संतोष सोनी के खिलाफ बलरामपुर, रामानुजगंज,अंबिकापुर और सूरजपुर सहित विभिन्न जिलों में चेक बाउंस एवं लेनदेन विवाद से जुड़े कई मामले न्यायालय में लंबित बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वाहन खरीद-बिक्री और अन्य लेनदेन में रकम लेने के बाद भुगतान के नाम पर चेक दिए जाते थे, जो खातों में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण बाउंस हो जाते थे। कई लोगों के लाखों रुपए फंसे होने की भी चर्चा है।

फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर सीआरपीएफ में भर्ती हुआ आरक्षक गिरफ्तार

बलरामपुर का कूटरचित दस्तावेज लगाकर हासिल की थी नौकरी,बर्खास्तगी के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार,मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच जारी

-संवाददाता-
बलरामपुर,14 मई 2026
(घटती-घटना)।

फर्जी निवास प्रमाण-पत्र बनवाकर सीआरपीएफ में नौकरी हासिल करने वाले एक आरक्षक को बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को सीआरपीएफ से बर्खास्त किए जाने के बाद पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने फर्जी तरीके से निवास प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी पाने की बात स्वीकार कर ली। जानकारी के अनुसार तहसीलदार बलरामपुर द्वारा 28 अप्रैल 2026 को थाना बलरामपुर में लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में बताया गया कि 204 कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ करनपुर जगदलपुर में पदस्थ कांस्टेबल सुमित पिता अचल सिंह द्वारा तहसील कार्यालय बलरामपुर के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनवाया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने विशाल सोनी पिता स्वर्गीय सुरेश सोनी के शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में कूट रचना कर अपने नाम से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करवाया था। यही फर्जी प्रमाण पत्र सीआरपीएफ में भर्ती के दौरान भी प्रस्तुत किया गया था।

जांच में खुली फर्जीवाड़े की परतें : मामले की शिकायत मिलने के बाद थाना बलरामपुर में अपराध क्रमांक 78/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को दस्तावेजों में कूटरचना, फर्जी निवास प्रमाण पत्र तैयार करने और उसका उपयोग सरकारी नौकरी हासिल करने में किए जाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (2), 319(2), 336 (3), 340 (2), 61(2)(ए), 338 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(सी) एवं 66(डी) के तहत अपराध दर्ज किया है। विवेचना के दौरान 14 मई 2026 को 204 कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ करनपुर जगदलपुर से आरोपी आरक्षक को विधिवत बर्खास्त किए जाने के बाद पुलिस ने अभिरक्षा में लिया।

सोशल मीडिया वीडियो के बाद मौत... अब कई सवालों के घेरे में अमन ओझा केस

डेढ़ माह पहले जताई थी जान का खतरा,जांच के लिए बनाई गई विशेष टीम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 मई 2026
(घटती-घटना)।

शहर के मिशन चौक निवासी और टुनटुन दाबेली संचालक अमन ओझा की झारखंड में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत अब कई सवाल खड़े कर रही है। मौत से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो, पुलिस को दी गई शिकायत और कलेक्टर को सौंपे गए आवेदन के बाद यह मामला अब केवल एक सामान्य मौत नहीं माना जा रहा है। जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों की मांग के बाद आईजी ने पूरे मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित की है। दरअसल 10 मई को झारखंड के रंका क्षेत्र में अमन ओझा का शव मिला था। शव मिलने की परिस्थितियां शुरू से ही संदेह पैदा कर रही थीं। चेहरे पर चोट के निशान थे और शव की स्थिति को लेकर भी कई सवाल उठे। घटना के बाद से परिजन और परिचित हत्या की आशंका जता रहे हैं। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब अमन ओझा के सोशल मीडिया वीडियो सामने आए। अप्रैल माह में पोस्ट किए गए इन वीडियो में अमन ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी और बेटी को एक धर्म विशेष का युवक अपने साथ ले गया है। उसने यह भी कहा था कि विरोध करने पर उसे धमकियां मिल रही हैं और उसकी हत्या कराई जा सकती है। अमन ने कुछ युवकों के नाम और मोबाइल नंबर भी पुलिस को दिए थे। बताया जा रहा है कि मौत से तीन दिन पहले अमन ने कलेक्टर को लिखित शिकायत देकर सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत देने के दो दिन बाद ही उसका शव झारखंड में मिला। ऐसे में अब यह सवाल उठ रहा है कि यदि शिकायतों को गंभीरता से लिया जाता तो क्या घटना टल सकती थी। मामले में भाजपा पार्षद आलोक दुबे और सरगुजा सर्व ब्राह्मण समाज ने भी जांच की मांग उठाई। इसके बाद आईजी दीपक झा ने विशेष जांच टीम गठित की है। टीम में अंबिकापुर सीएसपी राहुल बंसल, कोतवाली थाना प्रभारी शशिकांत सिन्हा और रामानुजगंज थाना प्रभारी को शामिल किया गया है। इधर अमन की पत्नी ने किसी अन्य युवक से संबंध होने की बात से इनकार किया है। उसका कहना है कि घरेलू विवाद और मारपीट के कारण वह अलग रह रही थी। हालांकि उसने भी पति की मौत को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब पूरे मामले में लोगों की नजर जांच टीम की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि यह हत्या है,दुर्घटना या फिर इसके पीछे कोई और वजह है।

पेड़ के नीचे बैठकर बेच रहा था गुड़,डंगाल गिरने से वृद्ध की मौत

-संवाददाता-
लखनपुर,14 मई 2026
(घटती-घटना)।

लखनपुर में पीपल पेड़ के नीचे एक वृद्ध गुड़ बेच रहा था। तभी तेज आंधी में पेड़ का डंगाल टूटकर उसके ऊपर गिर गया और वह घायल हो गया। लखनपुर अस्पताल से रेफर करने पर अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मिनकेतन प्रधान उम्र 62 वर्ष दरिमा थाना क्षेत्र के ग्राम खजुरी का रहने वाला था। वह बुधवार को साप्ताहिक बाजार लखनपुर में गुड़ बेचने गया था। वह पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ बेच रहा था। तभी दोपहर करीब 3 बजे तेज आंधी शुरू हो गई। तेज आंधी के कारण पीपल पेड़ का डंगाल टूटकर उसके ऊपर गिर गया। इससे वृद्ध गंभीर रूप से जख्मी हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए लखनपुर अस्पताल ले गए।

जैव विविधता एवं वेटलैंड संरक्षण पर संभाग स्तरीय कार्यशाला सम्पन्न

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 मई 2026
(घटती-घटना)।

अम्बिकापुर सरगुजा वनमंडल के काष्ठागार में गुरुवार को 'जैव विविधता एवं वेटलैंड' संरक्षण विषय पर एक दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य लोगों में जैव विविधता संरक्षण और वेटलैंड के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद चिंतामणि महाराज उपस्थित रहे। उन्होंने 'जल है तो कल है' का संदेश देते हुए स्टॉप डैम एवं चेक डैम के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही मैनपाट क्षेत्र के जलाशयों एवं प्रदूषण मुक्त वेटलैंड संरक्षण पर बल दिया। कार्यक्रम में उपस्थित लुण्ड्रा विधायक श्री प्रबोध मिंज ने कहा कि जंगल एवं पर्यावरण संरक्षण केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। कार्यशाला में टेंगुपुर बांध को प्रस्तावित रामसर वेटलैंड साइट के रूप में विकसित करने के प्रयासों की जानकारी भी दी गईइसके साथ ही जैव विविधता प्रबंधन समिति , पीबीआर एवं स्थानीय जैव संसाधनों के संरक्षण तथा Access and Benefit Sharing (ABS) संबंधी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता

लोक निर्माण विभाग सेतु मण्डल अम्बिकापुर (छ0ग0)
बाबूपारा जेल रोड़ अम्बिकापुर फोन 07774-224498 फैक्स 224113

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना
Portal:https://eproc.cgstate.gov.in

निम्नलिखित कार्य हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है -
निविदा डाउनलोड करने की अंतिम तिथि - दिनांक 31.05.2026
निविदा आमंत्रण - प्रथम आमंत्रण

स0 क्रं0	निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक व दिनांक	सिस्टम निविदा क्र.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3	4	5
1	01/ 11.05.2026	190659	लोक निर्माण विभाग सेतु उपसंभाग अम्बिकापुर अंतर्गत विशुनपुर-तेलाईधार मार्ग पर मांड नदी पर निर्मित पुल में विशेष मरम्मत कार्य का निविदा आमंत्रण बावत् ।	रू. 19.67 लाख

जी नंबर-262700679/3

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग सेतु मण्डल
अम्बिकापुर (छ0ग0)

जिला शिक्षा अधिकारी ने बतौली के व्याख्याता सुरेश कुमार जायसवाल की संविदा नियुक्ति की समाप्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 मई 2026
(घटती-घटना)।

जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा ने आदेश जारी कर कार्रवाई करते हुए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बतौली के संविदा व्याख्याता सुरेश कुमार जायसवाल की संविदा नियुक्ति समाप्त कर दी है। प्राप्त जानकारी के सुरेश कुमार जायसवाल की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया था कि सम्बंधित 24 अप्रैल की मध्यरात्रि में आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई थी। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि वायरल वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति सुरेश कुमार जायसवाल ही है तथा प्रयुक्त वाहन भी उनका ही था। जांच प्रतिवेदन में कहा गया कि इस घटना से विद्यालय की गरिमा को गहरा आघात लगा एवं शिक्षा विभाग की छवि भी धूमिल हुई। आदेश के अनुसार सुरेश कुमार जायसवाल का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम,1965 के नियम-3 के तहत निर्धारित कर्तव्यों के प्रतिकूल, अत्यंत गंभीर, निंदनीय एवं दंडनीय है। यह कृत्य सेवा में बने रहने हेतु इनकी पात्रता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है तथा नियुक्ति आदेश के कण्डिका-5 का स्पष्ट उल्लंघन करने पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर सुरेश कुमार जायसवाल का कार्य-व्यवहार संतोषप्रद नहीं पाये जाने के कारण संविदा नियुक्ति समाप्त कर दी गई है।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

रा0प्र0क्र0 /20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सरोज देवी आ0/पति राजेन्द्र कुमार यादव व अन्य 02 जाति, निवासी दर्रीपारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला - दर्रीपारा, शीट नम्बर 10 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3922 / 2 रकबा 0.05 1/4 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 25/05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांक- 22/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील) नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

रा0प्र0क्र0 /20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेश कुमार सिंह आ0 / पति विक्रम सिंह जाति निवासी डी0सी0 रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला - महावीर वार्ड, शीट नम्बर-4 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1893/4777/11 रकबा 0.03 1/2 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 25 /05/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 08/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील) नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

रा0प्र0क्र0 /अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक ननकू आ. चमरू व अन्य निवासी ग्राम बरढोढी तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम बरढोढी स्थित भूमि खसरा नंबर 335/1, 368/1, 457, 458, 459, 460, 461, 650, 713/1, 715, 727, 729 रकबा 0.490, 0.137, 0.121, 0.065, 0.093, 0.024, 0.008, 0.238, 0.181, 0.169, 0.190, 0.470 हे0 कुल खसरा नंबर 12 कुल रकबा 2.186 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखों में पंजीबद्ध हक त्यागनामा दिनांक 17.03.2026 के माध्यम से अनावेदकगण का नाम विलोपित करते हये आवेदकगण का नाम यथावत रखे जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 25.05.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक- 05/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

(सील) तहसीलदार अंबिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

रा0प्र0क्र0 /अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पप्पू अग्रवाल आ0 देवी प्रसाद अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी सत्तीपारा अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम सुभाषनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 18/14 रकबा 0.016 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखो में पंजीबद्ध दान पत्र दिनांक 13.04.2026 के माध्यम से नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 29.05.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक:- 13/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

(सील) तहसीलदार अंबिकापुर,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगांव जिला-सूरजपुर,छ.ग.

ईश्तहार

रा0प्र0क्र0 /ब-121/2025-26

आम जनता ग्राम बतरा को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुरेन्द्र सिंह आ0 स्व0 सोनसाय जाति गोड निवासी ग्राम बतरा तहसील भटगांव जिला सूरजपुर छ0ग0 द्वारा अपने पिता स्व0 सोनसाय आठ स्व0 धीरसाय का मृत्यु दिनांक 10/04/2004 को ग्राम बतरा घर में मृत्यु होना बताकर मृत्यु प्रमाण पत्र के पंजीयन बावत मय आवेदन, शपथ पत्र, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की प्रति सहित स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म/मृत्यु) का रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश) निगम 1969 के नियम 10 (13) के अन्तर्गत निर्देश देने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मृतक स्व0 सोनसाय आठ स्व0 धीरसाय का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 21/05/2026 को समय 11.00 बजे इस न्यायालय मे अपना अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति दावा प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि बाद प्राप्त आपत्ति / दावा पर कोई विचार नही किया जावेगा। तद्नुसार कार्यवाही कर दी जावेगी ।

आज दिनांक 06/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(सील) कार्यपालिक दण्डाधिकारी भटगांव,जिला-सूरजपुर

CMYK

मनेन्द्रगढ़ महाजुआ कांड में जितना जुआ नहीं पकड़ा गया उससे ज्यादा कहानी पकड़ी गई!

कोतवाली,सुपर कॉप और होटल कनेक्शन की अंदरूनी पटकथा चर्चा में...

सारे जगह बंद होगा...हमारे यहां नहीं! – आखिर किसके दम पर इतना भरोसा?

जुए से ज्यादा अब सेटिंग सिस्टम पर उठ रहे सवाल

मनेन्द्रगढ़ में जुए का खेल या संरक्षण का महाखेल?

कोतवाली की कुर्सी बदली...और शहर में फिर लौट आया कथित अवैध कारोबार!

112 से शुरू हुआ सफर...शहर के कथित नेटवर्क तक कैसे पहुंचा सुपर कॉप?

कार्रवाई हुई या सिर्फ कहानी का ट्रेलर दिखाया गया?

आईजी की सख्ती नहीं होती तो क्या दब जाता पूरा मामला?

होटल,हार-जीत और संरक्षण.... सबसे चर्चित पटकथा!

कमाऊ सिस्टम के आरोपों में घिरी कोतवाली पुलिस

मनेन्द्रगढ़ बनेगा अवैध कारोबार का गढ़ या टूटेगा संरक्षण का जाल?

कोतवाली की सेटिंग कथा में सुपर कॉप,होटल और संरक्षण की परतें चर्चा में...

-संवाददाता-
मनेन्द्रगढ़, 14 मई 2026
(घटती-घटना)।

मनेन्द्रगढ़ शहर इन दिनों किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लग रहा,फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर्दे पर नहीं,असल जिंदगी में किरदार घूम रहे हैं,कोई सुपर कॉप बनकर व्यवस्था की नसों में घुसा बैठा है, कोई होटल की आड़ में कथित कारोबार का केंद्र बना हुआ है,कोई संरक्षण के दम पर सीना ठोक रहा है और कोई कार्रवाई करके भी सवालों के घेरे में है।

सबसे मजेदार बात यह है कि जितना जुआ पुलिस ने पकड़ा,उससे कहीं ज्यादा कहानी लोगों के हाथ लग गई,शहर की चाय दुकानों में इस वक्त आईपीएल से ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज की है,तो वह है मनेन्द्रगढ़ महाजुआ कांड की अंदरूनी पटकथा की है, लोग पूछ रहे हैं अगर सब कुछ अचानक पकड़ा गया,तो फिर महीनों से शहर में चर्चा क्यों थी? अगर पुलिस अनजान थी,तो पत्रकारों और आम लोगों तक जानकारी कैसे पहुंच रही थी? और अगर जानकारी थी,तो फिर कार्रवाई इतनी देर से क्यों हुई? यानी सवाल इतने हैं कि जवाब देने वाला भी शायद अब जवाब ढूंढ रहा होगा।

जब पत्रकारों को पता था,तो पुलिस को कैसे नहीं?

यही सवाल अब सबसे ज्यादा उठ रहा है,अगर शहर के पत्रकारों,आम नागरिकों और चाय दुकानों तक कथित गतिविधियों की चर्चा पहुंच चुकी थी, तो फिर पुलिस आखिर क्या कर रही थी? क्या वाकई जानकारी नहीं थी? या जानकारी होने के बावजूद आंखें बंद थीं? शहर के लोग अब तंज कस रहे हैं–कोतवाली के कैमरे शायद सिर्फ हेलमेट चेक करने के लिए चालू रहते होंगे।

आईजी ने पहले ही पहचान लिया था खेल?

सूत्र बताते हैं कि पूर्व सरगुजा रेंज के आईजी पहले ही संबंधित प्रधान आरक्षक की कार्यशैली को लेकर सतर्क थे, बताया जा रहा है कि उन्होंने उसकी पूरी कार्यप्रणाली की फाइल तैयार कर उसे जिले से बाहर भेजा था, लेकिन फिर बल की कमी का तर्क आया और साहब की वापसी हो गई, अब लोग व्यंग्य में कह रहे हैं–जिसे बाहर भेजा गया था सुधार गृह की तरह, वह अपग्रेड होकर वापस आ गया।

जो उसके करीब गया,वही बदनाम हुआ...

पुलिस विभाग के भीतर भी यह चर्चा है कि उक्त प्रधान आरक्षक की शैली ऐसी है कि वह धीरे-धीरे अधिकारियों को अपने प्रभाव में ले लेता है, पहले दोस्ती...फिर सलाह...फिर कमाई मॉडल...और आखिर में पूरा सिस्टम उसी की लाइन पर चलने लगता है,यही वजह है कि अब शहर में यह कहा जा रहा है की कोतवाली में पोस्टिंग भले प्रभारी की हो, लेकिन रिमोट किसी और के हाथ में है।

इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई...या सबसे बड़ी अधूरी कहानी?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है की अगर पुलिस सचमुच पूरी नीयत से कार्रवाई करती, तो क्या यह जिले की सबसे बड़ी जुआ कार्रवाई बन सकती थी? लोगों का कहना है कि कथित नेटवर्क इतना बड़ा था कि उसकी सिर्फ सतह ही सामने आई है, कई नाम बच गए...कई चेहरे गायब रहे...और कई खिलाड़ी शायद पहले ही बाहर निकल गए,यानी कार्रवाई हुई जरूर,लेकिन सवाल यह है कि क्या पूरी हुई?

सरगुजा आईजी की सक्रियता बनी उम्मीद...

इस पूरे मामले में एक नाम ऐसा है,जिसे लेकर लोगों के बीच सकारात्मक चर्चा है वह नाम है आईजी दीपक झा,सूत्रों का कहना है कि लगातार निगरानी और दबाव की वजह से ही कार्रवाई आगे बढ़ पाई, लोगों का मानना है कि अगर उच्च स्तर से सख्ती नहीं होती,तो शायद मामला किसी फाइल में दबकर रह जाता।

मनेन्द्रगढ़ को अवैध कारोबार की राजधानी बनने से रोकना होगा...

आज सबसे बड़ा खतरा यही है कि अगर समय रहते सिस्टम में सुधार नहीं हुआ,तो मनेन्द्रगढ़ धीरे-धीरे अवैध कारोबारों का स्थायी केंद्र बन सकता है, जुआ...सट्टा.... कोयला...सेटिंग...संरक्षण...अगर यह सब एक ही छत के नीचे मिलने लगे,तो फिर कानून का डर खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगता।

सेटिंग है,कोई कार्रवाई नहीं होगी – आरोपी के कथित बयान ने बढ़ाई बेचैनी

सूत्रों के अनुसार पूछताछ में एक आरोपी ने कथित तौर पर कहा कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि पुलिस से सेटिंग है, कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब एडिशनल एसपी ने पूछा कि किसने कहा...तो आरोपी ने लल्ला,अजीत और मोहन नाम लिए,अब यही तीन नाम जिले की सबसे बड़ी चर्चा बन चुके हैं, लोग पूछ रहे हैं,कौन हैं ये लोग? क्या ये केवल खिलाड़ी थे? या पूरे नेटवर्क के मैनेजर? और सबसे बड़ा सवाल है की क्या पुलिस अब इन तक पहुंचेगी?

मुख्य सरगना मोहन आखिर कैसे बच निकला?

पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि मुख्य सरगना बताया जा रहा व्यक्ति बच निकला,जबकि पुलिस के पास टाइमिंग भी थी, जानकारी भी थी और पूरी रणनीति भी, तो फिर सरगना कैसे निकल गया? क्या उसे पहले से सूचना मिल गई थी? या फिर कार्रवाई इतनी नियंत्रित रखी गई थी कि बड़े नाम बच जाएं? लोग अब कह रहे हैं कि यदि राजा ही भाग गया, तो सैनिक पकड़कर क्या मिला?

पहला अध्याय...

जब कोतवाली में अंकुश नाम की चीज हुआ करती थी-सूत्र बताते हैं कि जब तक कोतवाली की कमान सुनील तिवारी के हाथ में थी,तब तक शहर में कथित जुआ कारोबार की हालत वैसी थी जैसे स्कूल में सख्त प्रिंसिपल के समय पिछली बेंच वाले छात्र की होती है,डर के साथ उपस्थिति,कहा जा रहा है कि जिस होटल में आज कथित तौर पर जुए का साम्राज्य फलता-फूलता दिखा, वहां तिवारी ने तीन-तीन बार दबिश दी थी,होटल संचालकों को साफ संदेश था–होटल चलाओ, होटल को कसीनो मत बनाओ। उस समय शहर में यह चर्चा थी कि कुछ लोग पुलिस सिस्टम के भीतर अपनी अलग दुकान खोलने की तैयारी कर रहे थे,लेकिन सुनील तिवारी उनकी राह में स्पीड ब्रेकर बने हुए थे।

सुपर कॉप की एंट्री : 112 से सीधे अंडरग्राउंड नेटवर्क

फिर कहानी में एंट्री होती है उस किरदार की, जिसे शहर के लोग अब व्यंग्य में सुपर कॉप कहकर बुला रहे हैं, सूत्रों की मानें तो उक्त प्रधान आरक्षक को 112 सेवा के लिए बुलाया गया था, लेकिन धीरे-धीरे उसकी सक्रियता ऐसी बढ़ी कि लोग कहने लगे –112 कम, 420 ज्यादा एक्टिव है। कहते हैं कि उसने शहर में अपने अलग संपर्क विकसित करने शुरू किए,कहीं होटल वालों से दोस्ती,कहीं अवैध कारोबारियों से तालमेल,कहीं पुलिस के भीतर पकड़ मजबूत करने का खेल, सब कुछ इतनी शांति से हुआ कि शहर को भनक तब लगी, जब कथित कारोबार फिर से पनपने लगा।

सुनील तिवारी क्यों दूरी बनाकर रखते थे?

सूत्रों के अनुसार सुनील तिवारी उस प्रधान आरक्षक की कार्यप्रणाली से पहले से परिचित थे,उन्हें अंदेशा था कि यदि उसे ज्यादा खुली छूट मिली, तो पूरा सिस्टम धीरे-धीरे कमाई मॉडल में बदल जाएगा, यही वजह बताई जा रही है कि उन्होंने उसे अपने करीब फटकने नहीं दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कीचड़ अगर जूते तक रहे तो धोया जा सकता है,लेकिन सिर तक पहुंच जाए तो आदमी पहचान में नहीं आता।

फिर बदला सिस्टम...और शुरू हुई नई पटकथा

कुछ समय बाद कोतवाली में बदलाव हुआ और दीपेश सैनी को जिम्मेदारी मिली, सूत्रों का दावा है कि यहीं से कथित रूप से बंद पड़े कारोबारों में फिर हलचल शुरू हुई,शहर में चर्चाएं शुरू हो गई कि अब सेटिंग का नया अध्याय खुल चुका है,कहते हैं कि पर्दे के पीछे पूरा संचालन वही चर्चित प्रधान आरक्षक संभाल रहा था,कौन कहां बैठेगा...किसे संरक्षण मिलेगा...किससे कितना लेना है...और किसे कब बचाना है...सबका मैनेजमेंट शुरू हो गया,हालांकि बाद में दीपेश सैनी का तबादला हो गया,लेकिन तब तक कथित नेटवर्क जड़ें जमा चुका था।

साइबर प्रभारी को मिला कोतवाली का प्रभार...और शुरू हुआ कमाऊ पुत्र मॉडल

इसके बाद जिस निरीक्षक को कोतवाली का अतिरिक्त प्रभार मिला, वह पहले से साइबर शाखा देख रहे थे,अब यहां कहानी और दिलचस्प हो जाती है,सूत्रों के अनुसार सुपर कॉप ने उन्हें ऐसा गुरुमंत्र दिया कि धीरे-धीरे पूरा अवैध नेटवर्क फिर सक्रिय होने लगा,शहर में व्यंग्य चल पड़ा साइबर वाले साहब को ऑफलाइन कमाई का ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल गया, कहा जा रहा है कि कथित तौर पर जुआ,सट्टा और अन्य अवैध कारोबारों को हरी झंडी इसी दौर में मिली।

नागपुर कनेक्शन : कोयला कारोबारी या नेटवर्क मैनेजर?

सूत्रों के अनुसार इस पूरी कहानी में एक नाम और चर्चा में है वह नाम नागपुर का कथित कोयला कारोबारी अंकित,लोगों का कहना है कि उसकी पहले से कुछ अधिकारियों के साथ मजबूत पकड़ थी और उसी पकड़ के दम पर शहर में कथित अवैध कारोबारों की नई नींव रखी गई,अब यह कितना सच है और कितना अफवाह,यह जांच का विषय है,लेकिन शहर में चर्चा इतनी तेज है कि लोग कहने लगे हैं मनेन्द्रगढ़ में कोयले से ज्यादा गर्मी अब सेटिंग से निकल रही है।

होटल बना मनोरंजन केंद्र?

शहर के बीच स्थित जिस होटल का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है,वहां कथित तौर पर पिता-पुत्र दोनों की भूमिका बताई जा रही है,सूत्रों के अनुसार पुत्र शहर के बीचोंबीच कथित जुआ संचालन देख रहा था, जबकि पिता किसी अन्य स्थान पर समान गतिविधियों से जुड़े बताए जा रहे हैं, सबसे हैरानी वाली बात वह कथित बयान है,जो अब शहर में वायरल चर्चा बन चुका है की सारे जगह जुआ बंद हो जाएगा, लेकिन हमारे यहां नहीं,अब सवाल यह है कि कोई इतनी छाती ठोककर यह बात आखिर किस भरोसे पर कह सकता है? क्या राजनीतिक संरक्षण? क्या पुलिस में मजबूत पकड़? या फिर दोनों?

अंतिम सवाल.... मनेन्द्रगढ़ शहर आज यही पूछ रहा है

क्या सचमुच जुआ खत्म होगा?

क्या संरक्षण पर कार्रवाई होगी?

क्या सिस्टम बदलेगा?

या फिर कुछ दिनों बाद नया होटल, नया ठिकाना और वही पुरानी पटकथा फिर शुरू होगी?

क्योंकि शहर अब समझ चुका है –यह सिर्फ जुए का मामला नहीं....यह उस सिस्टम की कहानी है, जहां कुछ लोग कानून से ज्यादा सेटिंग पर भरोसा करने लगे हैं।

कोरिया- सूरजपुर समाचार
अम्बिकापुर मंगलवार 12 मई 2026
5
आओ सुनाऊ मनेन्द्रगढ़ के महा जुआ कांड की कार्रवाई की पटकथा!
मनेन्द्रगढ़ जुआ कांड में शरीर रेड में, दिमाग संरक्षण में!
मनेन्द्रगढ़ के महाजुआ कांड की कार्रवाई की पटकथा!

घटती घटना
सरगुजा,सूरजपुर कोरिया समाचार
अम्बिकापुर सोमवार 11 मई 2026
4
आईजी के दौरे के बाद जागी पुलिस
मनेन्द्रगढ़ के जुआ फड़ पर दबिश से मचा हड़कंप
थाना मनेन्द्रगढ़
छपते-छपते

विशेष नोट

यह समाचार विभिन्न सूत्रों, स्थानीय चर्चाओं और घटनाक्रमों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर तैयार किया गया है,समाचार में उल्लिखित आरोपों एवं दावों की आधिकारिक पुष्टि शेष है, प्रस्तुत सामग्री का उद्देश्य जनचर्चा और घटनाक्रम को सामने लाना है।

अब सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं,सफाई का है...

एमसीबी जिले में अब सिर्फ छापेमारी से काम नहीं चलेगा, जरूरत उस पूरे नेटवर्क को तोड़ने की है,जो कथित तौर पर पुलिस, कारोबार और संरक्षण की तिकड़ी पर खड़ा बताया जा रहा है,जब तक विवादित चेहरों को सिस्टम से अलग नहीं किया जाएगा,तब तक हर कार्रवाई के बाद यही सवाल उठेगा –पकड़ा कितना गया...और बचाया कितना गया?

श्मशान की जमीन पर वन माफियाओं का तांडव!

मधला के श्मशान घाट में दिनदहाड़े पेड़ों की कटाई,ग्रामीणों में भारी आक्रोश

रक्षक ही बने भक्षक? – वन विभाग के कर्मचारी पुत्र और स्थानीय रसूखदार पर लगे गंभीर आरोप

-संवाददाता-
सोनहत/कोरिया, 14 मई 2026
(घटती-घटना)।

कोरिया जिले के विकासखंड सोनहत अंतर्गत ग्राम मधला इन दिनों एक ऐसे मामले को लेकर सुर्खियों में है, जिसने न सिर्फ वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि ग्रामीणों की आस्था और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता पैदा कर दी है,गांव के श्मशान घाट परिसर में लगे यूकेलिप्टस के दर्जनों पेड़ों की कथित अवैध कटाई ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है,ग्रामीणों का आरोप है कि दिनदहाड़े मशीनें लगाकर पेड़ों को गिराया गया, लेकिन जिम्मेदार विभाग तमाशबीन बना रहा,अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर श्मशान जैसी सार्वजनिक और संवेदनशील भूमि पर पेड़ों की कटाई किसके संरक्षण में हो रही थी?

ग्रामीणों के अनुसार ग्राम मधला के श्मशान घाट क्षेत्र में वर्षों पहले हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए गए थे,लेकिन अब वही पेड़ कथित लकड़ी तस्करों के निशाने पर आ गए हैं,सूत्रों का दावा है कि अब तक 30 से 40 पेड़ काटे जा चुके हैं, कटाई इतनी बेखौफ तरीके से हुई कि लोगों का कहना है –ऐसा लग रहा था मानो कोई सरकारी अनुमति लेकर पूरा सफाया किया जा रहा हो। ग्रामीणों का आरोप है कि जेसीबी और मशीनों की मदद से दिनदहाड़े कटाई की गई, लेकिन वन विभाग और प्रशासन की ओर से समय रहते कोई ठोस हस्तक्षेप नहीं हुआ।

सड़क जनता के लिए या तस्करों के लिए?

गांव में अब यही सवाल गूंज रहा है कि क्या सड़क निर्माण का फायदा जनता को मिलेगा या फिर लकड़ी माफियाओं को? ग्रामीणों का कहना है कि यदि अभी सख्ती नहीं हुई,तो आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के पेड़ साफ कर दिए जाएंगे,क्योंकि अब कटाई जंगलों से निकलकर श्मशान घाट तक पहुंच चुकी है।

खानापूर्ति वाली जांच पर उठे सवाल

ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग सिर्फ दिखावे की जांच कर रहा है,लोगों का कहना है कि अगर वास्तव में कार्रवाई करनी होती,तो मशीनें जब्त होतीं,लकड़ी कब्जे में ली जाती,आरोपियों पर एफआईआर दर्ज होती, नुकसान का आंकलन कर वसूली होती, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ,यही वजह है कि विभाग की नीयत और निष्पक्षता दोनों सवालों के घेरे में हैं।

सड़क स्वीकृत होते ही सक्रिय हुए तस्कर?

ग्रामीणों ने मामले में एक और गंभीर पहलू उठाया है, उनका कहना है कि कुशमाहा से मधला तक नई पक्की सड़क की स्वीकृति मिलते ही लकड़ी तस्करों की गतिविधियां बढ़ गई,ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क बनने से पहले ही तस्करों ने यह समझ लिया कि अब लकड़ी की ढुलाई आसान हो जाएगी, यानी विकास की सड़क आने से पहले ही तस्करों ने व्यापारिक संभावना तलाश ली।

ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

मामले को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त नाराजगी है,उन्होंने साफ कहा है कि यदि जल्द दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई और नुकसान की भरपाई नहीं कराई गई,तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा, ग्रामीणों का कहना है कि आज श्मशान की जमीन पर पेड़ कट रहे हैं,कल कोई और सार्वजनिक जमीन कब्जे में ले ली जाएगी, अगर अभी आवाज नहीं उठाई गई,तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा।

प्रशासन के सामने बड़ा सवाल

अब सबसे बड़ा सवाल प्रशासन और वन विभाग की भूमिका पर है, क्या वास्तव में निष्पक्ष जांच होगी? क्या नामजद लोगों पर कार्रवाई होगी? क्या कटे पेड़ों की भरपाई कराई जाएगी? क्या श्मशान भूमि को सुरक्षित घोषित कर निगरानी बढ़ाई जाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे,लेकिन फिलहाल ग्राम मधला में एक ही चर्चा है –हरे पेड़ों की हत्या हुई है...और जिम्मेदार अब भी खुले घूम रहे हैं।

आस्था पर चोट,ग्रामीणों में उबाल

श्मशान घाट सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं होता,वह समाज की आस्था, परंपरा और संवेदनाओं से जुड़ा स्थान होता है,ऐसे स्थान पर हरियाली उजाड़े जाने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है,लोगों का कहना है कि जिस जगह पर अंतिम संस्कार होते हैं,जहां लोग अपने पूर्वजों की स्मृतियों से जुड़े रहते हैं,वहां इस तरह पेड़ों की कटाई करना सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है,ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यदि समय रहते कटाई नहीं रोकी गई,तो पूरा श्मशान क्षेत्र उजड़ जाएगा।

दिनदहाड़े कटाई...आखिर किसकी शह पर?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सार्वजनिक भूमि पर इतनी बड़ी कटाई बिना संरक्षण के कैसे संभव है? ग्रामीणों का आरोप है कि यह सब किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में रसूखदार लोगों और विभागीय संरक्षण की बू साफ दिखाई दे रही है,लोग पूछ रहे हैं—अगर पेड़ अवैध रूप से काटे जा रहे थे, तो वन विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? और यदि जानकारी थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

नामजद शिकायत से मचा हड़कंप

मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब ग्रामीणों ने कलेक्टर कोरिया और डीएफओ बैकुंठपुर को सौंपे गए शिकायत पत्र में कुछ लोगों पर सीधे आरोप लगाए, ग्रामीणों का दावा है कि अवैध कटाई के पीछे गांव के ही एक प्रभावशाली जनप्रतिनिधि और वन विभाग के कर्मचारी के पुत्र की भूमिका है,यही आरोप अब पूरे मामले को और गंभीर बना रहे हैं, क्योंकि यदि ग्रामीणों की बात सही है,तो यह सिर्फ अवैध कटाई का मामला नहीं,बल्कि रसूख और विभागीय पहुंच के गठजोड़ का उदाहरण बन सकता है।

रक्षक के घर से ही भक्षक?

ग्रामीणों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर है कि जिस विभाग का काम जंगल और पेड़ों की रक्षा करना है,उसी विभाग से जुड़े लोगों के नाम अब कटाई मामले में सामने आ रहे हैं,लोग व्यंग्य में कह रहे हैं की अब जंगल बचाने वाले ही जंगल साफ करवाने में लगे हैं, यही वजह है कि ग्रामीणों का भरोसा विभागीय कार्रवाई पर कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है।

शिकायत के बाद भी नहीं रुकी कटाई?

ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहले ही स्थानीय प्रशासन और वन विभाग को मामले की जानकारी दे दी थी। लेकिन इसके बावजूद कटाई का काम जारी रहा,जब मामला बढ़ा और ग्रामीण सामूहिक रूप से शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे,तब जाकर विभाग की नींद टूटी,अगले दिन पटवारी और वन विभाग की टीम मौके पर जरूर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि यह कार्रवाई सिर्फ औपचारिक निरीक्षण बनकर रह गई,समाचार लिखे जाने तक किसी भी आरोपी के खिलाफ ठोस दंडात्मक कार्रवाई सामने नहीं आई थी।

बिना दस्तावेज लकड़ी परिवहन पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई

लकड़ी से भरा ट्रैक्टर जब्त,मामला वन मंडल मनेंद्रगढ़ भेजा गया

-संवाददाता-
एमसीबी/खड़गवां, 14 मई 2026
(घटती-घटना)।

जिले के खड़गवां वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने अवैध लकड़ी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लकड़ी से भरे एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में लकड़ी कारोबारियों के बीच हड़कंप की स्थिति बन गई है।

जानकारी के अनुसार पूछताछ में सुखनंदन सिंह पिता भगवान गिदमुड़ी ने वन विभाग को बताया कि वह किसानों से लकड़ी खरीदकर ट्रैक्टर के माध्यम से गौरेला स्थित एक आरा मिल में बेचने ले जा रहा था। बताया जा रहा है कि लकड़ी गौरेला के आरा मिल संचालक मोनू महराज के मिल में ले जाई जा रही थी।

दस्तावेज मांगने पर नहीं दिखा सके अनुमति पत्र

वन विभाग की जांच के दौरान चालक से लकड़ी परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज, ट्रांजिट पास और अनुमति पत्र मांगे गए, लेकिन वह किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, इसके बाद वन परिक्षेत्र अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लकड़ी सहित ट्रैक्टर को जब्त कर लिया, जप्त वाहन और लकड़ी को आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए वन मंडल मनेंद्रगढ़ भेज दिया गया है।

किसानों से खरीदी लकड़ी का रिकॉर्ड कहां?

कार्रवाई के बाद अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं, सूत्रों के अनुसार क्षेत्र में लंबे समय से बिना दस्तावेज लकड़ी परिवहन की शिकायतें मिल रही थीं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों से खरीदी गई लकड़ी का रिकॉर्ड कहां है और बिना वैध अनुमति के परिवहन आखिर कैसे किया जा रहा था? वन विभाग अब इस बात की भी जांच कर रहा है कि लकड़ी की खरीदी और परिवहन में कहीं किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका तो नहीं है।

वन विभाग की सख्ती से कारोबारियों में मचा हड़कंप

वन विभाग की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सक्रिय लकड़ी कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। माना जा रहा है कि विभाग आने वाले दिनों में अवैध लकड़ी परिवहन,बिना ट्रांजिट पास संचालित कारोबार और नियमों के उल्लंघन पर और सख्त अभियान चला सकता है,वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिना वैध दस्तावेज किसी भी प्रकार का लकड़ी परिवहन नियम विरुद्ध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

जिल्दा सहकारी समिति में खाद घोटाले की बू... रिकॉर्ड में टनभर खाद,गोदाम में पसरा सन्नाटा!

जांच से पहले रातों-रात भरे गए नए गोदाम ने बढ़ाया शक, करोड़ों की गड़बड़ी की आशंका से प्रशासन में हड़कंप

-राजेन्द्र शर्मा-
कोरिया/खड़गवां, 14 मई 2026
(घटती-घटना)।

जिले के जिल्दा ग्राम स्थित आदिम जाति सहकारी समिति में खाद भंडारण और स्टॉक में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है, किसानों के लिए रखी गई खाद के कथित घोटाले की शिकायत सुशासन तिहार के दौरान ग्रामीणों द्वारा की गई थी, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए।

ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन द्वारा सील किए गए चार गोदामों को जब अधिकारियों की मौजूदगी में खोला गया तो अंदर की स्थिति देखकर जांच टीम भी दंग रह गई, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कृषि विभाग और सहकारिता विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर खाद के रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक का मिलान किया, जिसमें भारी अंतर सामने आया।

रिकॉर्ड में 71.5 मीट्रिक टन यूरिया, मौके पर मिला केवल 54 टन!

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि रिकॉर्ड के अनुसार गोदाम में 71.5 मीट्रिक टन यूरिया होना चाहिए था, लेकिन मौके पर केवल लगभग 54 मीट्रिक टन ही मिला,वहीं डीएपी, पोटाश, एनपीके और एसएसपी खाद के स्टॉक में भी भारी कमी पाई गई, अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआती जांच का आंकड़ा है,वास्तविक स्थिति विस्तृत सत्यापन के बाद ही स्पष्ट होगी,सूत्रों की मानें तो खाद की कमी करोड़ों रुपए की गड़बड़ी की ओर इशारा कर रही है। यही वजह है कि प्रशासन अब पूरे मामले को गंभीर आर्थिक अनियमितता के रूप में देख रहा है।

जांच से पहले रातों-रात भरा गया नया गोदाम!

ग्रामीणों ने जांच टीम के सामने आरोप लगाया कि मामले की भनक लगते ही जांच से ठीक पहले रातों-रात एक नए गोदाम – मनोरंजन भवन – में खाद भरकर रखी गई, ताकि वास्तविक कमी को छिपाया जा सके, मौके पर जमीन में बिखरी खाद, अव्यवस्थित ढंग से रखी बोरियां और जल्दबाजी में किए गए भंडारण के संकेत ग्रामीणों के आरोपों को और मजबूत करते नजर आए, ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते जांच नहीं होती तो पूरा मामला दबा दिया जाता।

नियमों को ताक पर रखकर किया गया खाद का भंडारण

जांच में पहुंचे कृषि विभाग के एसडीओ धनंजय सोनी ने भी भंडारण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए, उन्होंने बताया कि अलग-अलग प्रकार की खाद को बिना किसी वर्गीकरण के एक साथ रख दिया गया था। कई जगह यूरिया और डीएपी मिश्रित अवस्था में मिले, जो भंडारण के नियमों का खुला उल्लंघन है, इतना ही नहीं, गोदामों में खाद के साथ भूसे की बोरियां तक रखी मिलीं, जिसे अधिकारियों ने गंभीर लापरवाही माना। अधिकारियों के मुताबिक इस तरह का अव्यवस्थित भंडारण न सिर्फ नियम विरुद्ध है बल्कि इससे खाद की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है।

हर सीजन में किसानों को बताया जाता था खाद खत्म

ग्रामीणों और किसानों का आरोप है कि समिति प्रबंधन वर्षों से किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं करा रहा था,हर सीजन में खाद की कमी का हवाला दिया जाता था, जबकि रिकॉर्ड में पर्याप्त स्टॉक दर्ज रहता था, किसानों का आरोप है कि खाद की कालाबाजारी कर निजी स्तर पर बिक्री की जाती रही और जरूरतमंद किसानों को खाद के लिए भटकना पड़ता था,अब जांच में सामने आई गड़बड़ी ने किसानों के आरोपों को और बल दे दिया है।

समिति प्रबंधक मोबाइल बंद कर हुआ गायब

मामले के केंद्र में आए समिति प्रबंधक अखिलचंद सिंह फिलहाल संपर्क से बाहर बताए जा रहे हैं, ग्रामीणों के अनुसार जांच शुरू होते ही उनका मोबाइल बंद हो गया और वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, इससे पूरे मामले में संदेह और गहरा गया है।

दोबारा सील हुए गोदाम,कलेक्टर को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

निरीक्षण के बाद प्रशासन ने सभी गोदामों को दोबारा सील कर दिया है, अधिकारियों का कहना है कि विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार कर कलेक्टर को सौंपी जाएगी, जिसके बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, अब बड़ा सवाल यही है कि किसानों के हक की खाद आखिर गई कहां? रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक के बीच इतना बड़ा अंतर सिर्फ लापरवाही है या फिर इसके पीछे लंबे समय से चल रहा कोई संगठित खेल? आने वाले दिनों में जांच की दिशा और प्रशासनिक कार्रवाई पर सबकी नजर टिकी हुई है।

CMYK

49 अवॉर्ड जीतने वाली वो फिल्म जिसे फ्लॉप मानकर सितारों ने लौटा दी थी फीस,बाद में निकली ब्लॉकबस्टर

दो दशक पहले आई वो फिल्म जिसके हिट होने की कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। इसके चलते सितारों ने अपनी फीस तक लौटा दी थी। फिल्में या तो मेकर्स को मालामाल बना देती हैं या फिर कंगाल। कई प्रोड्यूसर्स फिल्मों के चलते अर्श से फर्श तक पहुंच चुके हैं। दो दशक एक फिल्म आई थी जिसके फ्लॉप होने का डर प्रोड्यूसर्स के मन में ऐसा बैठा कि उन्होंने सितारों से फीस तक वापस मांग ली। जी हां, हिंदी सिनेमा की कल्ट क्लासिक फिल्म मानी जाने वाली फिल्म के सितारों ने प्रोड्यूसर्स को अपनी फीस लौटा दी थी। इस फिल्म ने 49 अवॉर्ड्स जीतकर इतिहास रच दिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी ब्लॉकबस्टर रही थी।

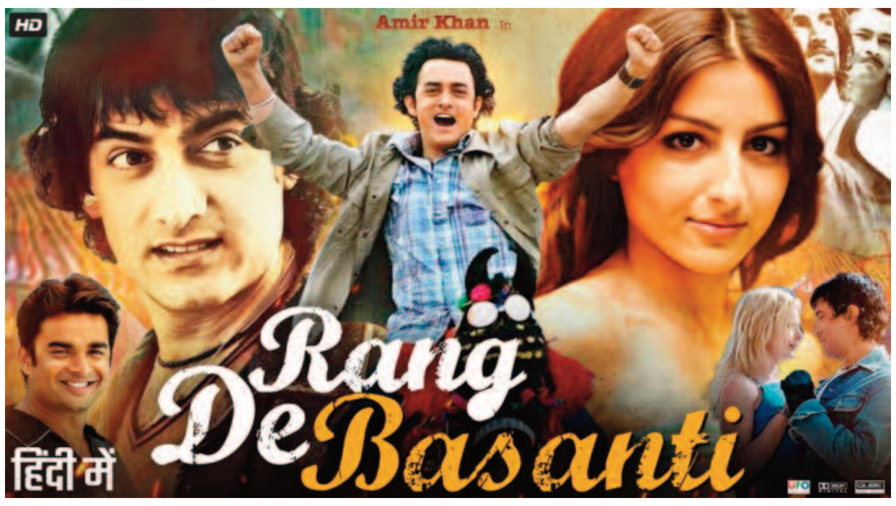

फ्लॉप मानी जा रही थी फिल्म

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं आमिर खान की कल्ट फिल्म रंग दे बसंती है। राकेश ओमप्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी रंग दे बसंती को उन्होंने डायरेक्ट करने के साथ-साथ रॉनी स्क्रूवाला संग प्रोड्यूस भी किया था।

फिल्म की कहानी ने छू लिया था दिल

2006 में रिलीज हुई फिल्म की कहानी एक ब्रिटिश फिल्म स्टूडेंट के इर्द-गिर्द घूमती है जो भारत आकर भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन के पांच स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी को डॉक्यूमेंट करने आती है। वह पांच नौजवानों से दोस्ती करती है और उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट करती है,जो उन्हें आज की सरकार के अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है। फिल्म में आमिर खान,आर माधवन,सिद्धार्थ,अतुल कुलकर्णी शरमन जोशी,कुणाल कपूर,ब्रिटिश एक्ट्रेस एलिस पैटन,वहीदा रहमान और सोहा अली खान अहम भूमिकाओं में थे। एक बार सोहा ने फिल्म से जुड़ा किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि प्रोड्यूसर्स को लगा कि फिल्म हिट नहीं हो पाएगी।

सितारों ने लौटा दी थी फीस

सोहा अली खान ने एक इंटरव्यू में कहा था, फिल्म के प्रमोशन के दौरान प्रोड्यूसर ने अचानक फोन किया और सभी से अपनी फीस लौटाने की गुजारिश की। उन्हें फिल्म को लेकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। सभी ने उनकी बात मान ली, लेकिन जब आखिरकार फिल्म रिलीज हुई तो इसने एक आंदोलन खड़ा कर दिया। हम सभी हैरान रह गए, यह फिल्म जगत में एक मील का पत्थर बन गई।

रंग दे बसंती का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

करीब 28 करोड़ रुपये के बजट में बनी रंग दे बसंती सिर्फ 28 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी, जबकि इस फिल्म ने दुनियाभर में करीब 97 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने नेशनल फिल्म अवॉर्ड, फिल्मफेयर, आईफा, जी सिने समेत 49 अवॉर्ड्स जीते थे।

एक्ट्रेस मौनी रॉय और सूरज नांबियार का तलाक कंफर्म

एक्ट्रेस ने लिखा...आपसी सहमति से अलग होने का फैसला

अभिनेत्री मौनी रॉय और उनके पति सूरज नांबियार के तलाक को लेकर पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं और कयास जारी थे। इसी बीच, अभिनेत्री ने गुरुवार को इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए सोशल मीडिया पर एक नोट जारी करके तलाक को कंफर्म कर दिया। इंस्टाग्राम पर नोट शेयर करते हुए अभिनेत्री ने आधिकारिक तौर पर पति से अलग होने की पुष्टि की।

अभिनेत्री ने अपने नोट में इस बात को स्पष्ट किया कि वे और सूरज पिछले काफी समय से मीडिया और सोशल मीडिया पर निजी जिंदगी को लेकर हो रही चर्चाओं से काफी असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने लिखा,हम अपने निजी जीवन में मीडिया के कुछ लोगों द्वारा की जा रही बेवजह दखलअंदाजी और ज्यादा ध्यान दिए जाने से दुखी हैं। साथ ही, सभी को बताना चाहते हैं कि हमने अलग होने का फैसला लिया है और इस समय को शांति और समझदारी के साथ निजी तौर पर संभालना चाहते हैं। अभिनेत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी निजी जिंदगी को लेकर कई झूठी बातें फैलाई जा रही थीं। उन्होंने लिखा,काफी समय से सोशल मीडिया पर हमारे निजी जीवन की बातें गलत तरीके से फैलाई जा रही हैं, जो हमारे रिश्ते की सच्चाई नहीं दिखाती। काफी सोच-विचार के बाद और अपनी बदलती प्राथमिकताओं को समझते हुए हमने आपसी सहमति से अलग रास्तों पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। मौनी रॉय ने यह भी लिखा,इस समय को हम दोनों ही शांतिपूर्वक और निजी तरीके से संभालने पर ध्यान दे रहे हैं। अभिनेत्री ने जोर देते हुए लिखा कि रिश्ता खत्म होने के बाद भी वे और सूरज उनके बीच दोस्ती को कायम रखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने लिखा, इस दौरान हमारी प्राइवेसी का सम्मान करने और हमें लगातार प्यार व समर्थन देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।

सैफ अली खान की कर्तव्य देखते ही शाहरुख खान हो गए थे इंप्रेस

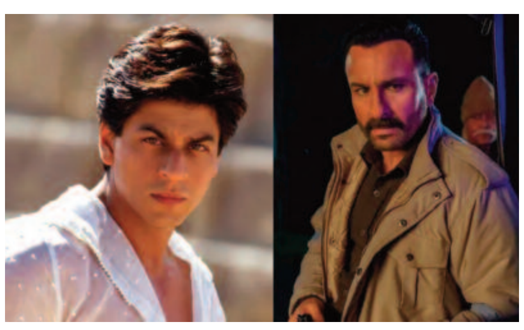

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान कर्तव्य मूवी में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म सिनेमाघरों की बजाय सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली है। फिल्म को देख शाहरुख खान और गौरी खान का क्या रिएक्शन था, इस बारे में सैफ ने बात की है।सैफ अली खान की फिल्म कर्तव्य का निर्माण शाह रुख और गौरी के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है। फिल्म का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही रिलीज किया गया था जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था।

शाह रुख को कैसी लगी फिल्म?

शाह रुख खान को भी कर्तव्य मूवी बहुत पसंद आई। उन्होंने रिलीज से पहले ही फिल्म देख ली है। सैफ अली खान ने बातचीत में बताया कि शाह रुख ने फिल्म देखने के बाद उन्हें क्या कहा। बकौल सैफ, ये कुछ ही शब्द थे, लेकिन बहुत ही अच्छे शब्द थे। फिल्म खत्म होने के बाद जो फीडबैक मिला, वह यह था कि उन्हें फिल्म सचमुच बहुत पसंद आई। मैं इसके लिए एक जबरदस्त रिलीज करवाने वाला हूं। यह कमाल की होगी।

क्या है फिल्म की कहानी?

सैफ अली खान की फिल्म कर्तव्य की कहानी एक पुलिस ऑफिसर की है जिसे नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ता है। मिल रहीं धमकियां उसके परिवार को खतरे में डाल देती हैं। अपनों की रक्षा और न्याय की सेवा करने की अपनी शपथ के बीच वह किसे चुनता है, कहानी इसी के इर्द-गिर्द घूमती है।

शोर से दूर रहकर ही कलाकार बेहतर काम कर सकते हैं : रकुल प्रीत सिंह

आज के समय में सोशल मीडिया कलाकारों के लिए यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां लोकप्रियता भी मिलती है और आलोचना भी। एक तरफ जहां फैंस अपने पसंदीदा सितारों से जुड़ पाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन ट्रोलिंग भी तेजी से बढ़ रही हैं। इसी मुद्दे पर अब अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने अपनी बेबाक राय रखी। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया के प्रभाव और उससे दूरी बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। रकुल प्रीत सिंह ने कहा, एक कलाकार के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह सोशल मीडिया पर चल रहे शोर और लगातार आने वाली प्रतिक्रियाओं से खुद को अलग रखना सीखे। अगर कोई कलाकार इंटरनेट पर लिखी हर बात को दिल से लगाने लगे,तो उसका असर उसके काम और मानसिक स्थिति दोनों पर पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि उनको अपनी ऊर्जा अपने काम पर लगानी चाहिए। रकुल ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तब सोशल मीडिया इतना व्यापक नहीं था। उस समय कलाकारों को आज की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मिलती थी, जिससे मानसिक दबाव भी कम रहता था। उस दौर में आलोचना और चर्चा का तरीका अलग था, जबकि आज के समय में हर व्यक्ति अपनी राय तुरंत और मुखर होकर सोशल मीडिया पर व्यक्त करता है।उन्होंने आगे कहा, कोरोना महामारी के बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। पिछले कुछ सालों में लोगों के पास ज्यादा समय था। इसका असर यह हुआ कि अब हर विषय पर लोगों की राय बहुत तेजी से सामने आती है और कलाकारों को लगातार आलोचना और टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। रकुल प्रीत सिंह ने कहा, एक अभिनेता को इस शोर से खुद को दूर रखना चाहिए।

काज़ी तौकीर और अरिजीत सिंह: वायरल तस्वीरों के पीछे की कहानी

जब 2000 के दशक की शुरुआत में रियलिटी शो ने पहली बार भारत के म्यूज़िक सीन को आकार देना शुरू किया, तो कई सिंगर रातों-रात सेंसेशन बन गए। कुछ ने लंबे समय तक चलने वाला करियर बनाया, जबकि कुछ लाखों दिल जीतने के बाद धीरे-धीरे लाइमलाइट से गायब हो गए। ऐसा ही एक नाम जो 90 के दशक के हर बच्चे को तुरंत याद होगा, वह है काज़ी तौकीर। स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स की पूरी पीढ़ी के लिए, उनके गाने जैसे %यह पल% एक इमोशनल एंथम बन गए।अब, सालों बाद, काज़ी फिर से सुर्खियों में हैं और इस बार, फेम गुरुकुल की यादें ताज़ा करने के लिए, साथ में कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह भी हैं। काज़ी तौकीर, जो 2005 के रियलिटी शो %फेम गुरुकुल% में अरिजीत सिंह के साथ दिखाई दिए थे, ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक दिल को छू लेने वाली रील शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने लंबे सफर को याद किया और सिंगर की इतनी बड़ी सफलता के बावजूद ज़मीन से जुड़े रहने के लिए तारीफ़ की। यह वीडियो फैंस को उनके शुरुआती रियलिटी शो के दिनों से लेकर काज़ी के हाल ही में पश्चिम बंगाल में अरिजीत के होमटाउन जियागंज के दौरे तक ले जाता है। रील में दोनों सिंगर्स जियागंज में एक साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए, स्कूटी पर शहर में घूमते हुए, लोकल लोगों से मिलते हुए और अपने बचपन के दिनों की यादें ताज़ा करते हुए दिख रहे हैं। काज़ी ने अरिजीत के परिवार, उनकी करीबी टीम और म्यूज़िक के अलावा उनके काम के बारे में भी प्यार से बात की।

खेल समाचार

श्रीलंका ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए टीम घोषित,तिलक वर्मा बने कप्तान

नई दिल्ली,14 मई 2026। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आगामी ट्राई सीरीज के लिए इंडिया ए टीम की घोषणा कर दी है। यह सीरीज श्रीलंका में खेली जाएगी, जिसमें भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें हिस्सा लेंगी। इस टूर्नामेंट के लिए बीसीसीआई ने युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा को टीम का कप्तान नियुक्त किया है। तिलक वर्मा को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम देते हुए यह जिम्मेदारी दी गई है।
टीम चयन में कई युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि बोर्ड भविष्य की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी कड़ी में युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में शामिल किया गया है, जो इस सीरीज में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। यह ट्राई सीरीज श्रीलंका में आयोजित की जा रही है, जहां तीनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगी। सीरीज का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के

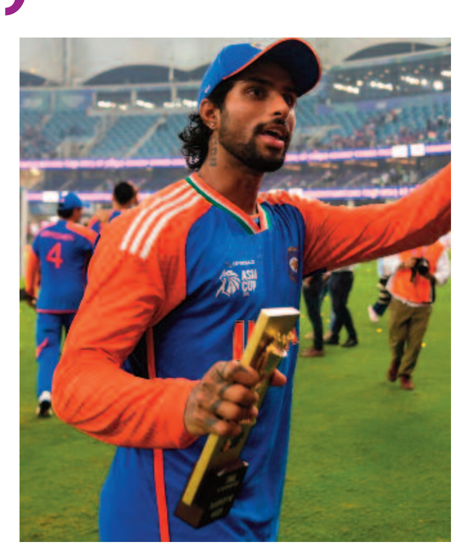

माहौल में अनुभव देना और उन्हें बड़े मंच के लिए तैयार करना माना जा रहा है।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल फ ॉर क्रिकेट इन इंडिया द्वारा घोषित इस टीम में संतुलित संयोजन देखने को मिला है, जिसमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में युवा प्रतिभाओं को अवसर दिया गया है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की ट्राई सीरीज युवा खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे उन्हें अलग-अलग परिस्थितियों में खेलने का अनुभव मिलता है। खासकर श्रीलंका जैसी परिस्थितियों में खेलना खिलाड़ियों के तकनीकी और मानसिक कौशल की परीक्षा लेता है। कप्तान तिलक वर्मा के नेतृत्व में इंडिया ए टीम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। टीम प्रबंधन का लक्ष्य इस सीरीज के जरिए भविष्य के लिए मजबूत खिलाड़ी तैयार करना है, जो आने वाले समय में सीनियर टीम में जगह बना सकें। फिलहाल क्रिकेट प्रेमियों की नजर इस ट्राई सीरीज पर टिकी हुई है, जहां भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।

मुंबई इंडियंस को युवाओं को मौका देने की सलाह

नई दिल्ली,14 मई 2026। मुंबई इंडियंस के प्लेऑफ की रेस से बाहर होने के बाद पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने टीम प्रबंधन को अहम सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि टीम अपने युवा खिलाड़ियों को अधिक मौके दे, ताकि वे अपनी ताकत और कमजोरियों को समझ सकें और अगले सीजन में बेहतर प्रदर्शन के साथ उतरें। पंजाब किंग्स के खिलाफ आगामी मुकाबले से पहले स्टार स्पोर्ट्स के 'क्रिकेट लाइव' कार्यक्रम में बात करते हुए गावस्कर ने कहा कि जब किसी टीम का सीजन लगभग खत्म हो चुका होता है, तो यह सही समय होता है युवाओं को परखने का और उन्हें अनुभव देने का। उन्होंने कहा कि इस तरह के मैचों में टीम मैनेजमेंट को परिणाम से ज्यादा भविष्य की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। उनके मुताबिक, युवा खिलाड़ियों को दबाव की स्थिति में खेलने का अनुभव मिलना चाहिए, ताकि वे बड़े मंच के लिए तैयार हो सकें। पंजाब किंग्स को लेकर बात करते हुए गावस्कर ने कहा कि टीम लगातार चार मैच हार चुकी है और अब जीत की पटरी पर लौटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि लगातार हार के बाद टीम में आत्मविश्वास की कमी आना स्वाभाविक है और ऐसे समय में खिलाड़ी और टीम प्रबंधन दोनों अलग-अलग विकल्पों पर विचार करने लगते हैं। गावस्कर ने यह भी कहा कि पंजाब किंग्स अब हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी, क्योंकि हार का सिलसिला टीम के मनोबल पर असर डालता है। उन्होंने संकेत दिया कि टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकती है या रणनीति में कुछ नया प्रयोग कर सकती है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान

जेम्स रियू और एमिलियो गे को मिला मौका

नई दिल्ली,14 मई 2026। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 4 जून से लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। जैक क्रॉली की जगह जेम्स रियू और एमिलियो गे को मौका मिला है। वहीं, ओली रॉबिन्सन की 2 साल से अधिक समय बाद वापसी हुई है। इंग्लैंड की यह टीम ऑस्ट्रेलिया में 4-1 से एशेज सीरीज हारने के बाद काफी बदली हुई नजर आ रही है। बेन स्टोक्स टीम के कप्तान होंगे।
मार्क वुड चोटिल होने के कारण उपलब्ध नहीं हैं। वहीं, ब्रायडन कार्स भी चोट के कारण टीम से बाहर हैं। वह इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी ज्यादा मैच नहीं खेल सके। पहले टेस्ट के लिए ऐसी है इंग्लैंड की टीम- बेन स्टोक्स (कप्तान), रेहान अहमद, गस एटकिंसन, सॉनी बेकर, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, बेन डकेट, मैथ्यू फिशर, एमिलियो गे, जेम्स रियू, ओली

रॉबिन्सन, जो रूट, जेमी स्मिथ (विकेटकीपर) और जोश टंग।
इंग्लैंड टीम प्रबंधन ने साफ किया है कि जोफ्रा आर्चर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। आर्चर अभी आईपीएल खेल रहे हैं और लंबे समय बाद उन्हें लाल गेंद क्रिकेट के लिए धीरे-धीरे तैयार किया जा रहा है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट 4 जून से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा टेस्ट 17 जून से द ओवल और तीसरा मुकाबला 25 जून से ट्रेंट ब्रिज में शुरू होगा।
गे प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 72 मुकाबले खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 124 पारियों में 40.18 की औसत से 4,702 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से 13 शतक और 18 अर्धशतक निकले हैं। 22 साल के जेम्स रियू ने अब तक 62 मुकाबले खेले हैं और इसकी 104 पारियों में 41.48 की औसत से 3,775 रन बनाने में सफल रहे हैं। उनके बल्ले से 12 शतक और 15 अर्धशतक निकले हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 221 रन रहा है। न्यूजीलैंड ने इस सीरीज के लिए पहले ही अपनी टीम घोषित कर दी है। वह आयरलैंड के खिलाफ भी एक टेस्ट खेलेगी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम- टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, जैक फोल्क्स, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, विल ओरूर्के, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, बेन सियर्स, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, केन विलियमसन और विल यंग।

नेशनल डबल्स स्कैश चैंपियनशिप : अभय-वेलवन,राहुल-सूरज सेमीफाइनल में पहुंचे

चेन्नई ,14 मई 2026। मौजूदा चैंपियन अभय सिंह और वेलवन सेंथिलकुमार ने तीसरी नेशनल डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप के पुरुषों के डबल्स इवेंट में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। गुरुवार को चेन्नई में इंडियन स्क्वैश एकेडमी में खेले गए मैच में, उन्होंने सीधे गेम्स में शानदार जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। टॉप-सीडेड जोड़ी ने क्वार्टरफाइनल में शुभम और वेदांत पटेल को 11-4, 11-2 से हराया। अभय मिश्रित डबल्स श्रेणी में भी दौर में बने रहे। इस साल उनकी नियमित जोड़ीदार अनाहत सिंह की गैरमौजूदगी के कारण, वे राधिका सीलन के साथ जोड़ी बनाकर खेल रहे हैं। दूसरी वरीयता प्राप्त इस जोड़ी को रवि दीक्षित और जेनेट विधि से कड़ी चुनौती मिली, लेकिन उन्होंने 10-12, 11-8, 11-9 से संघर्षपूर्ण जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। पहला गेम हारने के बाद अभय और राधिका ने शानदार वापसी की। दूसरे और तीसरे गेम के अहम पलों में उन्होंने जिस तरह से धैर्य बनाए रखा, उसी की बदौलत वे यह मैच जीतने में सफल रहे। पुरुषों के डबल्स के क्वार्टरफाइनल मुकाबलों में भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। रवि दीक्षित और विकास मेहरा ने एक कड़े मुकाबले में मैथ्यू गॉडविन और नवनीत प्रभु को 11-7, 10-12, 11-7 से हराया। वहीं,तमिलनाडु की जोड़ी गुहन सेंथिलकुमार और संदेश पीआर ने हरेंद्र संधू और ओम सेमवाल को 11-7, 2-11, 11-8 से हराकर अपनी शानदार लय को बरकरार रखा। दूसरी वरीयता प्राप्त राहुल बैथा और सूरज चांद ने दिनेश आर और मैयप्पन एल को 11-6, 11-6 से हराकर आसानी से सेमीफाइनल में जगह बनाई। महिला डबल्स मुकाबले में, अनुभवी और टॉप-सीडेड जोड़ी जोशना चिनप्पा और राधिका सीलन ने ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की। उन्होंने सहाना कलैवनन और संगममित्रा शनमुघम को 11-2, 11-7 से हराया। ग्रूप ए के एक और मैच में, अनन्या नारायण और अनिका दुबे ने उन्हीं विरोधियों को 11-2, 11-1 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। मिश्रित डबल्स इवेंट में भी टॉप-सीडेड जोड़ी वेलावन सेंथिलकुमार और जोशना चिनप्पा ने जोरदार शुरुआत की। इस अनुभवी जोड़ी ने रोशन राजकुमार और सहाना कलैवनन को 11-4, 11-5 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली।

दागियों पर मेहरबानी या सिस्टम की मजबूरी?

औषधि विभाग की प्रमोशन सूची ने खड़े किए बड़े सवाल

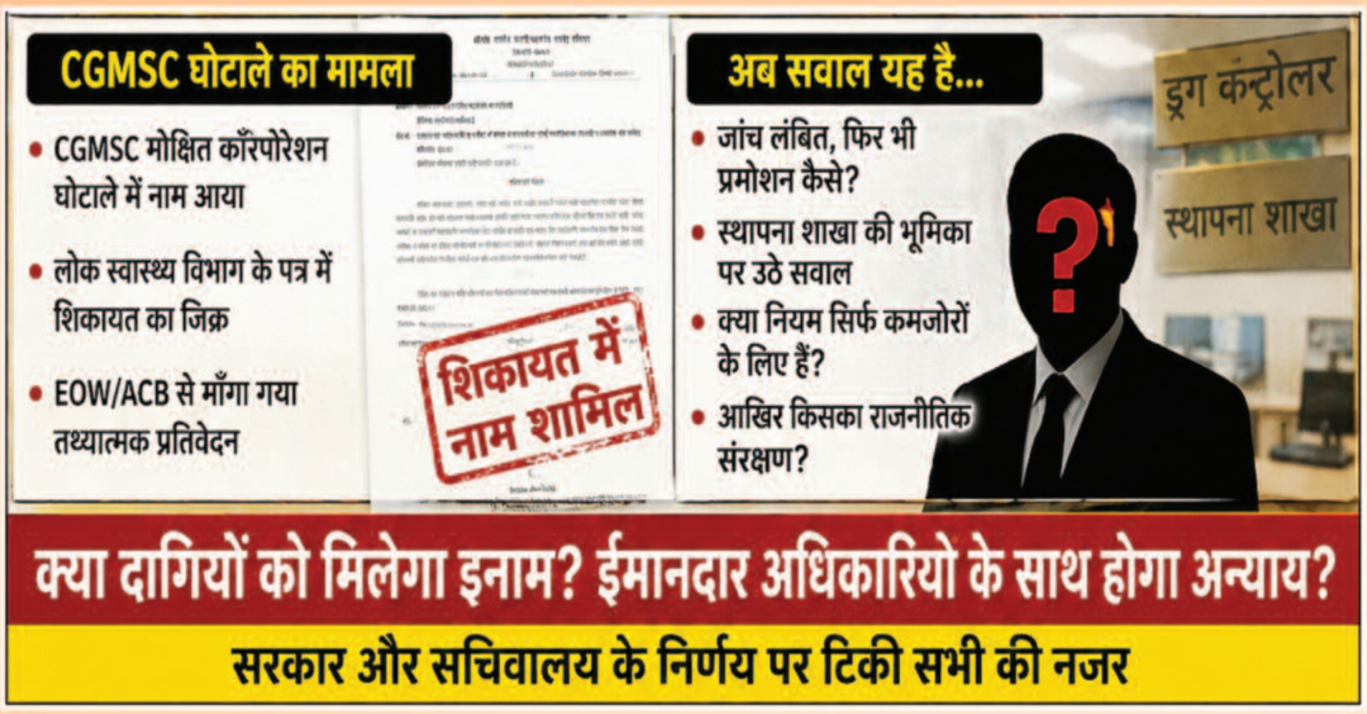

रिश्वत,घोटाले और जांच के साए में भी प्रमोशन की दौड़...आखिर किसका संरक्षण और किसका खेल?

80 हजार रिश्वत कांड के आरोपी और CGMSC घोटाले में नाम... फिर भी प्रमोशन की तैयारी!

दागियों को प्रमोशन? औषधि विभाग की सूची पर मचा बवाल!

रिश्वत,घोटाले और जांच के बावजूद प्रमोशन की दौड़ में अधिकारी!

एसीबी के शिकंजे से सचिवालय तक... आखिर किसके संरक्षण में चल रहा खेल?

औषधि विभाग में प्रमोशन या 'प्रबंधन'? विवादित नामों ने बढ़ाई सरकार की मुश्किलें

फाइल सचिवालय पहुंची,फिर लौटी वापस...क्या दागियों को बचाने की तैयारी?

स्थापना शाखा पर सवालः योग्य बाहर,विवादित अंदर?

दाग अच्छे हैं? औषधि विभाग की प्रमोशन सूची ने खड़े किए बड़े सवाल

- न्यूज डेस्क-

रायपुर 14 मई 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत औषधि प्रशासन विभाग इन दिनों किसी दवा नियंत्रण व्यवस्था से ज्यादा 'प्रमोशन प्रबंधन विभाग' के रूप में चर्चा में है, विभाग में एडीसी से डिप्टी ड्रग कंट्रोलर पद पर प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस प्रक्रिया ने अब कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं,वजह यह है कि जिन अधिकारियों के नाम भ्रष्टाचार,रिश्वतखोरी और कथित घोटालों में सामने आ चुके हैं,वही अधिकारी अब प्रमोशन सूची में चमकते दिखाई दे रहे हैं,विभागीय गलियारों में चर्चा यह नहीं है कि किस अधिकारी ने अच्छा काम किया, बल्कि यह है कि आखिर 'दागियों' के नाम सूची तक पहुंचे कैसे? और यदि पहुंचे भी,तो किसके संरक्षण में पहुंचे? सूत्रों की मानें तो इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में स्थापना शाखा,ड्रग कंट्रोलर कार्यालय और कुछ प्रभावशाली अधिकारी हैं,जिन पर आरोप लग रहे हैं कि वे नियमों की किताब को अपने हिसाब से पलट रहे हैं।

'दाग अच्छे हैं' वाला प्रशासनिक मॉडल?

विभागीय कर्मचारियों के बीच अब व्यंग्य में एक लाइन खूब चल रही है अब विभाग में दाग अच्छे हैं... कम से कम प्रमोशन के लिए,यह मामला केवल दो अधिकारियों का नहीं है,यह पूरे प्रशासनिक सिस्टम की पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता पर सवाल है,यदि रिश्वत और घोटाले के आरोपों से घिरे अधिकारी प्रमोशन पाते हैं, तो यह उन अधिकारियों के साथ भी अन्याय होगा जिन्होंने वर्षों तक बिना विवाद सेवा दी।

80 हजार की रिश्वत और फिर भी प्रमोशन की उम्मीद!

इस पूरे विवाद में सबसे चर्चित नाम है रविंद्र गेंदले का, वर्तमान में वे जांजगीर-चांपा में एडीसी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और अब डिप्टी ड्रग कंट्रोलर बनने की दौड़ में बताए जा रहे हैं,लेकिन सवाल यह है कि क्या विभाग इतना 'उदार' हो चुका है कि रिश्वत के आरोप भी अब प्रमोशन में बाधा नहीं रहे? मीडिया रिपोर्ट्स और विभागीय चर्चाओं के अनुसार रविंद्र गेंदले पर आरोप था कि उन्होंने एक निरस्त लाइसेंस को दोबारा बहाल करने के एवज में 80 हजार रुपये की मांग की थी,शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत एसीबी से की,बताया जाता है कि गेंदले ने रकम सीधे हाथ में लेने के बजाय अपने कार्यालय के पास स्थित एक दुकान में रखने को कहा था, बाद में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें रकम लेते समय गिरफ्तार किया,उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हुआ,मामला न्यायालय में विचाराधीन बताया जाता है,लेकिन विभागीय प्रमोशन सूची में नाम देखकर कर्मचारियों की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल है – 'क्या अब रिश्वतखोरी भी अनुभव की श्रेणी में गिनी जाएगी'?

CGMSC घोटाले की छाया और प्रमोशन का उजाला

दूसरा बड़ा नाम है हिरेन मनुभाई पटेल का,वर्तमान में वे राजनांदगांव जैसे बड़े जिले में एडीसी पद पर पदस्थ बताए जा रहे हैं, लेकिन उनका नाम कथित CGMSC मोक्षित कॉरपोरेशन भुगतान मामले में सामने आया था, अब इस मामले में सामने आए शासकीय पत्र ने विवाद को और गहरा कर दिया है, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन से जारी पत्र क्रमांक LAW-42018/25/2025-HEALTH SECTION-2 दिनांक 19 जनवरी 2026 में जीएम (टेक्निकल) हिरण हिरेन मनुभाई पटेल एवं जीएम (फाइनेंस) मिनाक्षी गौतम के खिलाफ शिकायत का उल्लेख किया गया है, पत्र में कहा गया कि 'Ms ANG Life Science India Ltd., Baddi' को नियम विरुद्ध तरीके से करोड़ों रुपये के भुगतान किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, इतना ही नहीं, पत्र में EOW/ACB से प्राप्त स्मरण पत्र का भी हवाला दिया गया है और मामले में तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा गया है, अब सवाल यह उठता है कि जब किसी अधिकारी का नाम शिकायत, जांच और EOW/ACB पत्राचार में दर्ज हो,तो फिर वह प्रमोशन सूची में कैसे शामिल हो सकता है? लेकिन विभाग में शायद नियमों की नई परिभाषा लिखी जा रही है — 'जांच चल रही है, इसलिए प्रमोशन रोकना उचित नहीं! '

हाईकोर्ट में मामला लंबित,फिर भी विभाग में सब 'सामान्य '?

शिकायत में सामने आए हाईकोर्ट दस्तावेजों के अनुसार मामला अभी भी विचाराधीन है, बिलासपुर हाईकोर्ट में 'छत्तीसगढ़ राज्य बनाम रविंद्र कुमार गेंडले 'शीर्षक से ACQA No.324/2019 लंबित बताया गया है,दस्तावेजों में यह भी दर्ज है कि FIR एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर में 2016 में दर्ज हुई थी, अब विभागीय कर्मचारियों के बीच व्यंग्य में कहा जा रहा है — 'अब शायद एसीबी केस भी प्रमोशन में बाधा नहीं,बल्कि अनुभव का हिस्सा माना जा रहा है। '

हिरण मनोहर भाई पटेल को 'विशेष संरक्षण' मिलने की चर्चा

सूत्रों के अनुसार कथित CGMSC घोटाले से जुड़े मामले में हिरण मनु भाई पटेल का नाम जांच एजेंसियों के दायरे में आ चुका है, विभागीय चर्चाओं में यह दावा किया जा रहा है कि शासन स्तर से जांच की अनुमति भी दी जा चुकी है और एसीबी/EOW की सूची में उनका नाम शामिल है, चर्चा यह भी है कि जांच एजेंसी को पूछताछ अथवा आगे की कार्रवाई का अधिकार प्राप्त है, लेकिन मामला अब तक निर्णायक स्तर तक नहीं पहुंच पाया,यही वजह है कि विभाग के भीतर 'विशेष संरक्षण' की चर्चा तेज हो गई है, कर्मचारियों के बीच यह सवाल पूछा जा रहा है कि जब किसी अधिकारी का नाम इतने बड़े वित्तीय अनियमितता प्रकरण से जुड़ चुका हो,तब भी उसे महत्वपूर्ण जिले में पदस्थापना कैसे मिल जाती है? व्यंग्य में विभागीय कर्मचारी कह रहे हैं - 'यहां घोटाले का आकार जितना बड़ा,पदस्थापना उतनी मजबूत! '

स्थानांतरण नीति भी प्रभाव के आगे कमजोर?

विभागीय सूत्रों के अनुसार बेनी राम साहू और रविंद्र कुमार गेंदले के मामले में भी स्थानांतरण आदेशों को लेकर कई चर्चाएं हैं,आरोप यह हैं कि इन अधिकारियों के लिए स्थानांतरण आदेश केवल कागज तक सीमित रह जाते हैं, बताया जा रहा है कि 29 जुलाई 2025 को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण आदेश जारी हुए थे,चर्चा यह भी है कि यह आदेश समन्वय स्तर से जारी हुआ था,जिसे विभागीय लोग 'विशेष निगरानी' वाला आदेश मान रहे थे, उस आदेश में बेनी राम साहू को उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला कोरिया भेजा गया था,वहीं रविंद्र कुमार गेंदले को उपसंचालक कार्यालय,खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जगदलपुर जिला बस्तर पदस्थ किया गया था,लेकिन विभागीय चर्चाओं के अनुसार दोनों अधिकारियों ने कथित तौर पर नए पदस्थापना स्थल पर जॉइनिंग नहीं की। बताया जा रहा है कि छुट्टी लेकर समय निकाला गया और बाद में कुछ समय पश्चात संशोधित आदेश जारी हो गए, अब विभागीय गलियारों में यही चर्चा है कि आखिर ऐसा प्रभाव किसके पास होता है कि शासन स्तर से जारी आदेश भी कुछ महीनों में बदल जाते हैं?

स्थानांतरण आदेश भी बेअसर?

संरक्षण के आगे सिस्टम बेबस होने की चर्चा-औषधि प्रशासन विभाग में चल रहे विवादों के बीच अब एक और गंभीर सवाल सामने आ रहा है,आखिर कुछ अधिकारियों पर शासन के आदेश भी प्रभावहीन क्यों दिखाई देते हैं? विभागीय सूत्रों और चर्चाओं के अनुसार जिन अधिकारियों के नाम विवादों,जांच और शिकायतों में सामने आए,उन्हीं अधिकारियों को न केवल महत्वपूर्ण पदस्थापनाएं मिलीं बल्कि स्थानांतरण आदेशों का पालन भी कथित तौर पर नहीं किया गया।

पहले आदेश निकलता है,फिर अधिकारी तय करते हैं जाना कहां है...

कर्मचारियों के बीच इस पूरे घटनाक्रम को लेकर व्यंग्य भी खूब चल रहा है,एक कर्मचारी ने तंज कसते हुए कहा सामान्य कर्मचारी आदेश मिलते ही रिलीव हो जाता है,लेकिन प्रभावशाली अधिकारी पहले आदेश देखते हैं,फिर तय करते हैं कि पालन करना है या आदेश ही बदलवाना है, यही कारण है कि अब विभाग में यह चर्चा सिर्फ प्रमोशन की नहीं,बल्कि प्रभाव,संरक्षण और प्रशासनिक निष्पक्षता की भी होने लगी है।

फाइल सचिवालय पहुंची...फिर वापस क्यों लौटी?

सूत्रों के मुताबिक प्रमोशन से जुड़ी फाइल ड्रग कंट्रोलर कार्यालय से सचिवालय तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वहां से फाइल को वापस भेजे जाने की चर्चा है, बताया जा रहा है कि सचिवालय स्तर पर कहा गया कि फाइल में 'टिप' लगाकर दोबारा भेजा जाए,अब विभाग में सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है,आखिर उस टिप में क्या लिखा जाएगा? क्या यह लिखा जाएगा कि अधिकारियों पर मामले लंबित हैं? क्या यह कि न्यायालय में सुनवाई जारी है? या फिर यह कि 'प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद प्रमोशन में कोई बाधा नहीं '? कर्मचारियों के बीच व्यंग्य में यह भी कहा जा रहा है कि शायद अब विभाग में प्रमोशन के लिए एसीबी या ईओडब्ल्यू की जांच 'अनुभव प्रमाण पत्र' की तरह मानी जाने लगी है।

अब निगाह सचिवालय और सरकार पर...

पूरा मामला अब सचिवालय और सरकार के अंतिम निर्णय पर टिका हुआ है,क्या विवादित नामों को सूची से हटाया जाएगा? क्या लंबित मामलों के निपटारे तक प्रमोशन रोका जाएगा? या फिर तकनीकी व्याख्याओं के सहारे सब कुछ 'नियमों के अनुरूप' बताकर आदेश जारी कर दिए जाएंगे? फिलहाल विभाग में सिर्फ एक ही चर्चा है — 'प्रमोशन योग्यता से मिलेगा... या पहुंच से?

स्थापना शाखा पर उठते सवाल

पूरा मामला अब स्थापना शाखा और वहां पदस्थ अधिकारियों की भूमिका पर आकर टिक गया है, विभागीय सूत्रों के अनुसार स्थापना देख रहे बेनी साहू का नाम भी चर्चाओं में है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रमोशन सूची तैयार करने में विवादित अधिकारियों को विशेष प्राथमिकता दी गई,विभाग के भीतर यह भी चर्चा है कि जिन अधिकारियों का रिकॉर्ड साफ है,उनके नाम पीछे कर दिए गए, जबकि प्रभावशाली और विवादित अधिकारियों के नाम सूची में आगे बढ़ाए गए,एक कर्मचारी ने व्यंग्य में कहा — 'अब विभाग में ईमानदारी नहीं,पकड़ मजबूत होना जरूरी है। '

क्या विभाग में नियम सिर्फ कमजोरों के लिए हैं?

यह सवाल अब सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है,क्योंकि सामान्य कर्मचारी के खिलाफ छोटी सी शिकायत भी उसके प्रमोशन, वेतनवृद्धि और सेवा रिकॉर्ड पर असर डाल देती है, लेकिन यहां ऐसे नाम सूची में हैं जिन पर भ्रष्टाचार और करोड़ों के भुगतान अनियमितता जैसे आरोप लग चुके हैं, तो क्या नियम सिर्फ छोटे कर्मचारियों के लिए हैं? क्या प्रभावशाली अधिकारियों के लिए अलग व्यवस्था चल रही है? क्या विभागीय जांच और एसीबी कार्रवाई अब केवल औपचारिकता बनकर रह गई है?

क्या प्रमोशन अब निष्पक्षता नहीं, पहुंच का खेल बन गया है?

यह मामला केवल दो अधिकारियों तक सीमित नहीं है,यह पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है,क्योंकि यदि रिश्वत और घोटाले के आरोपों से घिरे अधिकारी प्रमोशन पा जाते हैं, तो इसका सीधा संदेश यह जाएगा कि व्यवस्था में ईमानदारी की कोई कीमत नहीं बची,विभागीय कर्मचारियों में नाराजगी भी देखी जा रही है,कई कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों तक बिना किसी विवाद के सेवा देने वाले अधिकारियों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि विवादित अधिकारी 'विशेष कृपा' का लाभ उठा रहे हैं।

सिस्टम का नया फॉर्मूला आरोप लगते रहेंगे,प्रमोशन चलते रहेंगे!

यदि सूत्रों की बात सही है और विवादित अधिकारियों को प्रमोशन देने की तैयारी वास्तव में चल रही है,तो यह प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है,व्यंग्य में कर्मचारी कह रहे हैं-

- 'पहले सेवा रिकॉर्ड देखा जाता था,अब संपर्क रिकॉर्ड देखा जाता है।
- 'ईमानदार अधिकारी फाइल ढूंढते रह जाते हैं और प्रभावशाली अधिकारी प्रमोशन आदेश।
- 'अब विभाग में दाग अच्छे हैं...कम से कम प्रमोशन के लिए। '

सरकार के सामने बड़ी चुनौती

अब सबसे बड़ा सवाल सरकार और सचिवालय के सामने है,क्या विवादित नामों को प्रमोशन सूची से हटाया जाएगा? क्या लंबित मामलों के निपटारे तक प्रक्रिया रोकी जाएगी? या फिर तकनीकी व्याख्याओं के सहारे सब कुछ सामान्य बताकर प्रमोशन आदेश जारी कर दिए जाएंगे? यदि ऐसा होता है,तो यह केवल विभागीय विवाद नहीं रहेगा, बल्कि सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी छवि पर भी बड़ा सवाल खड़ा करेगा।

आखिर संदेश क्या जाएगा?

यदि रिश्वत प्रकरण में पकड़ा गया अधिकारी और घोटाले में नाम आने वाला अधिकारी प्रमोशन पा जाते हैं,तो इससे विभाग के भीतर क्या संदेश जाएगा? क्या युवा अधिकारी यह मान लें कि जांच और आरोप सिर्फ समाचारों तक सीमित हैं? क्या ईमानदार कर्मचारी यह समझ लें कि सिस्टम में टिके रहने के लिए काम नहीं, 'प्रबंधन' जरूरी है? और क्या जनता यह माने कि विभागीय कार्रवाई सिर्फ दिखावा है? यही वे सवाल हैं जिनका जवाब अब केवल विभाग नहीं, बल्कि सरकार को भी देना होगा।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)